RNI No. : TNHIN/2013/52520 | वर्ष - 13 | अंक - 348 | पृष्ठ - 8 | रु. 5/- | चेन्नई » गुरुवार » 16-07-2026 | www.dakshinbharat.com | Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 युवा आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है : आदित्यनाथ

6 क्या भारत विरोध ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट में धकेला?

7 मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए : अंजना सुखानी

फर्स्ट टेक

अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य के ग्रेटर तुंब द्वीप पर हवाई हमले किए

दुबई/एपी। अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने बुधवार को कहा कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ग्रेटर तुंब द्वीप पर ईरान के रक्षा और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। यह द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिस पर ईरान ने 1971 में उस समय कब्जा कर लिया था जब संयुक्त अरब अमीरात मौजूदा स्वरूप में नहीं था। अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने कहा कि उसने द्वीप पर लक्षित ठिकानों पर 90 मिनट तक हवाई हमले किए। उसने कहा, इन हमलों से होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता कमजोर हुई है।

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से 99 प्रतिशत निर्यात शुल्क-मुक्त हो जायेगा : शाह

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) श्रम-प्रधान उद्योगों में छिपी संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है, जिससे देश के 99 प्रतिशत निर्यात को बगैर-शुल्क (जीरो-ड्यूटी) बाजार पहुंच मिलेगी। शाह ने कहा कि बुधवार से लागू होने वाला यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना वाले विकसित भारत' की कुंजी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''यह समझौता श्रम-प्रधान उद्योगों में मौजूद कई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। इससे भारतीय निर्यात का 99 प्रतिशत हिस्सा शुल्क-मुक्त हो जायेगा, जिनमें कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र शामिल हैं।

राहुल गांधी को अदालत से मिली राहत

सुलतानपुर/भाषा। सुलतानपुर जिले की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनकी आवाज के नमूने की जांच का आदेश देने का आग्रह किया गया था। वादी पक्ष ने विशेष अदालत के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उनके राहुल गांधी द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने से जुड़े मामले में अदालत ने बुधवार को याचिका खारिज की।

सूर्यास्त 16-07-2026	सूर्योदय 17-07-2026
6:39 बजे	5:52 बजे

BSE	NSE
77,185.43 (+130.49)	24,078.50 (+ 26.46)

सोना	चांदी
15,108 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	231,000 रु. प्रति किलो

राजनीतिक मतभेदों से कहीं बड़ा होता है लोकतंत्र : उपराष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/भाषा। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने लोकतंत्र को राजनीतिक मतभेदों से कहीं बड़ा बताते हुए बुधवार को कहा कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन जनप्रतिनिधियों को जनता और संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। वह यहां राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत 'विधान गौरव यात्रा भूतपूर्व एवं वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन' के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, पूर्व व वर्तमान सदस्यों का यह अद्वितीय समागम एक सशक्त संदेश दे रहा है कि संस्थाएं व्यक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और लोकतंत्र राजनीतिक मतभेदों से कहीं बड़ा होता है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन कम से कम एक चीज ऐसी है जिसके प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता होनी चाहिए और वह है जनता और संविधान के प्रति हमारी निष्ठा। उन्होंने कहा, मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में अक्सर कहा करता हूं कि बहस, चर्चा और कभी-कभी व्यवधान भी अंततः किसी न किसी निर्णय पर पहुंचने का माध्यम होना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव तो जनता के वोटों से जीते जा सकते हैं लेकिन उनके दिल को जीतने के लिए उनकी सेवा करनी होगी। उन्होंने कहा, चुनाव के समय हम जनता के मतों से चुनाव जीतते हैं लेकिन उनके दिलों को हम तभी जीत सकते हैं जब जी-जान से उनकी सेवा करें। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जनता की सेवा कर पा रहे हैं या नहीं।

विधायकों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से विधानसभा में संचित अनुभव व ज्ञान आपको केवल किताबों में नहीं मिलेगा, यह उन लोगों के अनुभवों में जीवित रहता है जिन्होंने इस सदन की ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा की है। उन्होंने कहा, जब वरिष्ठ विधायक अपने अनुभव युवा सदस्यों के साथ बांटते हैं तो वे दरअसल संसदीय मूल्यों की मशाल अगली पीढ़ी को सौंप रहे होते हैं। नए व युवा विधायकों से तैयारी के साथ सदन में पहुंचने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा, खूब तैयारी करिए और जिस किसी भी समिति के आप सदस्य हैं वहां पर आप जनता के कल्याण के लिए क्या योगदान कर सकते हैं यह देखिए।

राधाकृष्णनन ने कहा, आज हम केवल एक संस्था का उत्सव नहीं मना रहे हैं। हम दरअसल उस विचार का उत्सव मना रहे हैं जिसके तहत लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब लोग एक साथ आकर गरिमा के साथ विचार विमर्श करते हैं और राष्ट्र हित को अपने हितों से उपर रखते हैं। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाउ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद थे।

प्रेस की आजादी के बिना कोई भी लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता: पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की स्वतंत्रता का सर्वोच्च महत्व है और सवाल पूछने का अधिकार ही कानून के शासन का मूल आधार है। राष्ट्रीय राजधानी में डिजिटल समाचार मंच 'डायनामाइट न्यूज' के नये स्टूडियो के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई भी लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता।

उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की स्वतंत्रता का सर्वोच्च महत्व है। स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई भी लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता। उन्होंने हालांकि इस बात पर भी जोर दिया कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रेस अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे। जब प्रेस अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तब वह प्रेस की स्वतंत्रता के सही उद्देश्य के विरुद्ध काम करता है। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने का अधिकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का केंद्रीय तत्व है। उन्होंने कहा, किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सवाल पूछने का अधिकार कानून के शासन का मूल आधार है और संविधान सवाल पूछने के अधिकार की गारंटी देता है।

सेमीकंडक्टर, मोबाइल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में सेमीकंडक्टर परिवेश को मजबूत बनाने, मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के तौर पर स्थिति मजबूत करने के लिए लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये के व्यय वाली दो बड़े विनिर्माण कार्यक्रमों को मंजूरी दी। सरकार ने सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये के 'सेमीकॉन 2.0' कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, मोबाइल फोन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और स्थानीय मूल्य सृजन को मजबूत करने के मकसद से 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन विनिर्माण' योजना को भी मंजूरी दी गई है।

सेमीकंडक्टर कार्यक्रम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के पहले चरण पर आधारित है। यह छह मुख्य क्षेत्रों... चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री, फैब्रिकेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक पैकेजिंग और परीक्षण, शोध और विकास तथा प्रतिभा विकास पर ध्यान देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, इस कार्यक्रम के अंत तक हम स्वदेशी चिप के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि नई योजना से लगभग चार लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा और योजना अवधि के दौरान दो लाख करोड़ रुपये मूल्य का सेमीकंडक्टर उत्पादन होगा।वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन 'विनिर्माण योजना' को भी मंजूरी दी है। इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक यानी पांच वर्षों के लिए विनिर्माताओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) दिए जाएंगे। पात्र मोबाइल फोन की बिक्री पर प्रोत्साहन 2.25 प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक होंगे। साथ ही मुख्य कलपुर्जे की घरेलू खरीद और उत्पाद डिजाइन और शोध में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।

सरकार को उम्मीद है कि मोबाइल फोन योजना से योजना अवधि के दौरान लगभग 39 लाख करोड़ रुपये का कुल उत्पादन होगा, निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और लगभग 60,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। भारत मोबाइल फोन विनिर्माण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब देश में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन यहीं बनते हैं। 2025 में मोबाइल फोन भारत का सबसे अधिक निर्यात होने वाला उत्पाद बन गया। इसने डीजल और तराशे हुए हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया।

सेमीकॉन 2.0 का मकसद सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा, वाणिज्यिक और रणनीतिक चिप डिजाइन और विभिन्न क्षेत्रों में जरूरी महत्वपूर्ण कलपुर्जे बनाने की क्षमता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टर मशीनरी, सामग्री, रसायन और गैस बनाने वाली कंपनियों को मदद देगा और साथ ही भारत में और फैब्रिकेशन संयंत्र लाने की कोशिश करेगा।

बैठक

संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी, आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और समिति के अन्य सदस्य बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 'एक देश, एक चुनाव' प्रस्ताव पर समिति की बैठक के बाद एक सामूहिक तस्वीर के लिए पोज़ देते हुए।

पुरी रथयात्रा के लिए तैयार, ओडिशा सरकार 'हाई अलर्ट' पर

पुरी/भाषा। ओडिशा में समुद्र के किनारे बसे पुरी शहर में बृहस्पतिवार को भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन की वार्षिक रथ यात्रा के लिए तीन शानदार लकड़ी के रथ 'ग्रैंड रोड' पर निकलने को तैयार हैं। इस बड़े आयोजन के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की कि तीनों रथों, भगवान बलभद्र के 'तालध्वज', देवी सुभद्रा के 'दर्पदलन' और भगवान जगन्नाथ के 'नंदीघोष' का निर्माण और सजावट पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि देवताओं से 'आज्ञामाला' (अनुमति का संकेत देने वाली माला) मिलने के बाद इन रथों को 12वीं सदी के इस मंदिर के 'सिंहद्वार' तक ले जाया गया। मंदिर के सामने 'ग्रैंड रोड' पर कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों रथ खड़े हैं। बृहस्पतिवार को देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालु रथ खींचने की प्रक्रिया देखेंगे। एसजेटीए के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढी ने बुधवार को पत्रकारों को बताया, महाप्रभु (भगवान जगन्नाथ) की कृपा से प्रशासन बृहस्पतिवार को सालाना रथ यात्रा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तैयारी में ओडिशा पुलिस के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल जैसे विभिन्न सरकारी विभाग भी शामिल हैं। इस बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी इंतजाम कर लिये गये हैं।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) संजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और त्वरित कार्यबल (आरएएफ) के कमांडो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) के जवानों समेत केंद्रीय सशस्त्र बलों की 15 कंपनियां (लगभग 1,500 जवान) और 13,000 पुलिसकर्मी पहले ही तैनात किए जा चुके हैं तथा समुद्र तट पर 500 लाइफगार्ड' भी तैनात किए गए हैं।

प्रदर्शन कर रहे मनरेगा श्रमिकों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया

खन्ना/भाषा। पंजाब के खन्ना में बुधवार को राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे मनरेगा श्रमिकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया, आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। प्रदर्शनकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लंबित भुगतान जारी करने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे।

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, पुलिस की कार्रवाई में 10 से अधिक मनरेगा श्रमिक घायल हो गए, जिन्हें फौरन खन्ना सिविल अस्पताल और विभिन्न निजी अस्पतालों में ले जाया गया। मनरेगा श्रमिक बुधवार सुबह खन्ना स्थित प्रेम भंडारी पार्क में जुटे और फिर अमलोह रोड स्थित सोंड के आवास की ओर मार्च किया।

आज की राजनीति में प्रतिशोध है, भाषा का स्तर गिरा : वसुंधरा राजे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/भाषा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इंसानियत को राजनीति की लक्ष्मण रेखा से बड़ी बताते हुए बुधवार को कहा कि आज राजनीति में प्रतिशोध है और भाषाई स्तर गिरा है। वह यहां राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। एक किस्से के का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पूर्व सांसद डॉ.अबरार अहमद के निधन पर मैं कांग्रेस कार्यालय पहुंचीं तो मेरे कुछ शुभचिंतकों ने कहा कि मेरा कांग्रेस कार्यालय जाना उचित नहीं। तब मैंने अपने शुभचिंतकों से कहा, 'इंसानियत... राजनीति की लक्ष्मण रेखा से बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने राजनीतिक सौहार्द का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने जिनेवा में पाकिस्तान द्वारा पेश किए मानवाधिकार हनन प्रस्ताव को रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, लेकिन अब राजनीति में प्रतिशोध है....भाषाई स्तर गिरा है। उन्होंने कहा, दुश्मनी तो जमके करो लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दो ताकि जब कभी हम एक दूसरे के सामने आएं तो हमें शर्मिंदा न होना पड़ा।

ममता ने बगावत के बीच अभिषेक का समर्थन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले कई बागी नेताओं द्वारा अभिषेक बनर्जी पर कथित मनमानी का आरोप लगाए जाने के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी बुधवार को अपने भतीजे के समर्थन में मजबूती से खड़ी नजर आईं। ममता ने 'गद्दारों की ओर से' लोगों से माफी मांगी और कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने कभी राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए समझौता किया। ममता बनर्जी ने कड़े तेवर दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर केंद्रीय जांच एजेंसियों और पुलिस का इस्तेमाल कर नेताओं से दल बदलवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह तृणमूल कांग्रेस को फिर से शुरू से खड़ा करेंगी। ममता ने साथ ही आरोप लगाया कि उनके विरोधी उन्हें मरता हुआ देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, वे चाहते थे कि मुझे दिल का दौरा पड़े। लेकिन मैं तब तक जिंदा रहूंगी, जब तक तुम्हारा अंत नहीं देख लेती।

पूर्व मुख्यमंत्री ने तृणमूल में फूट के बाद अभिषेक बनर्जी का जोरदार तरीके से बचाव करते हुए कहा कि उनके भतीजे को पार्टी पर 'हमला करने का बहाना' बना दिया गया है। ममता ने कहा कि अभिषेक और उनके परिवार के सदस्यों को बार-बार तलब किया गया लेकिन उन्होंने समझौता कर राहत पाने की बजाय राजनीतिक लड़ाई जारी रखना चुना। पूर्व मुख्यमंत्री ने 'फेसबुक' पर लाइव के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, अभिषेक बनर्जी को एक बहाना बना दिया गया है। उनके परिवार के सदस्यों को तलब किया गया। अगर वह चाहते तो राहत पा सकते थे, लेकिन वह मैदान छोड़कर नहीं भागे। जिस तरह उन्होंने लड़ाई जारी रखी, उससे उनकी सारी कमियां माफ हो गईं। वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा के नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट का दामन थामने के बाद ममता बनर्जी ने यह बयान जारी किया। मदन मित्रा, पार्टी छोड़ने के लिए अभिषेक बनर्जी की कथित मनमानी को जिम्मेदार ठहराने वाले तृणमूल कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं में शामिल हो गए। मित्रा ने कहा था कि उन्होंने इसलिए पार्टी छोड़ी क्योंकि अभिषेक बनर्जी को छह महीने के लिए 'पद से हटाने' की उनकी मांग ठुकरा दी गई थी।

ममता बनर्जी ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि मदन मित्रा के पार्टी छोड़ने की वजह मंगलवार को उनकी पत्नी और दो बेटों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से भेजा गया समन था।

दिल्ली में यमुना नदी 225 सालों में बहुत सिमटी

नई दिल्ली/भाषा। वर्ष 1799 के उस नक्शे ने यमुना नदी के अतीत को समझने का एक नया जरिया दिया है, जिसमें यमुना ज्यादा चौड़ी और मुक्त दिखाई देती है। अपने तरह के ऐसे पहले अध्ययन में, शोधकर्ताओं को यह पता लगाने में मदद मिली है कि दिल्ली में 200 से ज्यादा वर्षों में समय, मानव दखल और शहरीकरण की वजह से नदी पर क्या असर पड़ा है।

अध्ययन में सामने आया कि दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी की चौड़ाई करीब 68 प्रतिशत कम हो गई है। वहीं, नदी का बहाव भी लगभग 89 प्रतिशत घट गया है। यह शोध दिल्ली विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भोपाल के वैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने अपजॉन द्वारा 1799 में तैयार किए गए और राष्ट्रीय अभिलेखागार में सरंक्षित एक पुराने नक्शे, अन्य ऐतिहासिक नक्शों और आधुनिक उपग्रह तस्वीरों की मदद से यमुना के पुराने स्वरूप का अध्ययन किया।

अध्ययनकर्ताओं में शामिल प्रोफेसर विमल सिंह ने कहा, ''लोगों ने दिल्ली वाले हिस्से में यमुना नदी में हुए बदलावों के बारे में तो बात की है, लेकिन इस समय-सीमा के दौरान इसके बहाव में हुए बदलावों के बारे में किसी ने बात नहीं की है।''

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

भले ही हों

सोनम मरे जिये या उनका,
बॉडी वीक भले ही हों।
जिम्मेदार नहीं सरकारें
पेपर लीक भले ही हों।
बहरी हैं सारी सत्ताएं,
मांगे ठीक भले ही हों।
कॉकरोच मसले जायेंगे,
नीयत नीक भले ही हों।।

वायनाड में भूस्खलन के बाद बचाव, राहत कार्य प्रभावी ढंग से किया गया : सतीशन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को कहा कि हाल ही में वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद राज्य सरकार ने बचाव, राहत एवं पुनर्वास का काम प्रभावी ढंग से किया। उन्होंने मंत्रियों और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों की भी सराहना की। सतीशन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि आपदा के बाद सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी काम प्रभावी ढंग से पूरे किए गए। उन्होंने वायनाड भूस्खलन के बाद वहां किए गए कार्यों के लिए राजस्व मंत्री एपी अनिल कुमार और कृषि मंत्री टी सिद्दीक की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई आपदाओं में कुछ समय बाद तलाश अभियान बंद कर दिया जाता था लेकिन वायनाड में सभी आठ शव बरामद होने तक अधिकारियों ने अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि भूस्खलन के दौरान जान गंवाने वाले राज्य के बाहर के लोगों के परिजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सतीशन ने कहा कि सरकार ने विशेष विमान की व्यवस्था सहित शवों को उनके पैतृक स्थानों तक ले जाने का भी इंतजाम किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास का काम शुरू कर दिया गया है और चिन्हित खतरे वाले इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों ने कोंकण रेलवे और उसकी सहयोगी कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार ने संबंधित कंपनी के साथ समझौता भी किया है, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से घोषित मुआवजे के अलावा कंपनी पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देगी।

मंदिर जाना मेरा निजी अधिकार है, 'उदार हिंदुत्व' नहीं : केरल के मुख्यमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने कोल्लूर मूकांबिका मंदिर की अपनी हालिया यात्रा को लेकर लगाए गए 'उदार (सॉफ्ट) हिंदुत्व' के आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि उनकी आस्था उनका निजी मामला है, जिसे संविधान के तहत संरक्षण प्राप्त है। सतीशन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि वह पिछले 37 वर्षों से कर्नाटक स्थित इस मंदिर में (पूजा-अर्चना के लिए) जा रहे हैं तथा केवल इस आधार पर उन्हें उदार हिंदुत्व'' का नेता बताना पूरी तरह निराधार है।

उन्होंने कहा, ''मूकांबिका मंदिर जाना मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। मुझे भगवान में आस्था रखने का संवैधानिक अधिकार है। इसे 'उदार हिंदुत्व' कैसे कहा जा सकता है?'' मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 1990 के दशक से इस मंदिर में जाते रहे हैं। उन्होंने खुद को वहां की अधिष्ठात्री देवी का भक्त बताया। उन्होंने कहा, ''मैं पिछले 37 वर्षों से मूकांबिका मंदिर जा रहा हूं। मैं कोल्लूर मूकांबिका का भक्त हूं और यह बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है।''

सतीशन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यदि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया होता, तो यह अस्वाभाविक बात होती। उन्होंने आलोचकों पर पलटवार करते हुए कहा, ''वे किस दुनिया में रह रहे हैं?'' उन्होंने आरोप लगाया कि उनके आलोचक उन सभी लोगों का अपमान कर रहे हैं, जो पूजा-अर्चना के लिए धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। उन्होंने कहा, ''अधिकतर लोग मंदिर, चर्च और मस्जिद जाते हैं। क्या कोई यह कह सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे मंदिर जाना बंद कर देना चाहिए?'' सतीशन ने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधी अपनी ही पार्टी की अंदरूनी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके (विरोधियों के) पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे हताशा में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।

मुंबई में कोस्टल रोड पर सुरंग में एक कार में आग लगी, कोई हताहत नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। मुंबई में 'कोस्टल रोड' की सुरंग के अंदर बुधवार दोपहर एक कार में आग लग गई जिससे वहां वाहन चालकों में घबराहट फैल गयी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि आग बुझाने में करीब 20 मिनट लगे और इस बीच अन्य गाड़ी वाले दहशत में आ गए। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

अधिकारियों का कहना है कि जलती हुई कार के पीछे कई गाड़ियां फंस गईं, जिससे कुछ देर के लिए सड़क पर अफरातफरी मच गई।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह घटना दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर हाजी अली से वर्ली की ओर जाने वाली 'साउथबाउंड टनल' में हुई। उन्होंने कहा कि चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद अग्निशमन दल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तथा 108 एम्बुलेंस सेवा को भी भेजा गया। उन्होंने कहा कि आग बुझाने में करीब बीस मिनट का समय लगा। उन्होंने कहा कि आग की वजह का तत्काल पता नहीं चल पाया है। आग बुझ जाने के बाद सुरंग में गाड़ियों की आवाजाही बहाल हो गयी। एक चश्मदीद ने इस घटना को एक सबसे भयावह अनुभव बताया है। 'फेडरेशन ऑफ़ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन' के अध्यक्ष वीरेन शाह ने कहा, ''कुछ ही सेकंड में यातायात थम गया और लोग अपनी कारें छोड़कर भागने लगे। चारों तरफ चीख-पुकार, घबराहट और अफरातफरी का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो हॉलीवुड की किसी विध्वंसकारी फिल्म का दृश्य हो।'' जब आग लगी तब शाह भी उसी सुरंग के अंदर अपनी गाड़ी चला रहे थे। शाह ने कहा कि उस समय सुरंग के अंदर पूरी तरह अफरातफरी मची गयी थी, वह एक गाड़ी वाले से लिफ़्ट लेकर वर्ली तक पहुंचे और फिर दक्षिण मुंबई जाने के लिए टैक्सी ली।

शाह ने महाराष्ट्र सरकार से सुरंग के अंदर आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने की अपील की, जिसमें निकासी संबंधी संकेतों में सुधार, जन जागरूकता और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने वाहन चालकों के लिए आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने के तरीके जानने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

दिल्ली में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी, 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा को बुधवार को आगे बढ़ा दिया और अब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन अब पांच अगस्त के बजाय 17 अगस्त को किया जाएगा। इसी तरह, घर-घर जाकर सत्यापन करने की प्रक्रिया अब आठ अगस्त तक जारी रहेगी, जो पहले 29 जुलाई तक के लिए निर्धारित थी।

दिल्ली एसआईआर के तीसरे चरण का हिस्सा है, जिसे 14 मई को शुरू किया था। तीसरा चरण पूरा होने के बाद, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अतीत में विभिन्न कारणों से एसआईआर कार्यक्रमों में अक्सर बदलाव देखने को मिले हैं।

यूसीसी पर मोहन यादव बोले, यदि रामचंद्र एक विवाह करता है, तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंदौर/भाषा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार विधानसभा के 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विधेयक लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि देश में अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिए और अगर रामचंद्र नामक कोई व्यक्ति एक शादी करता है, तो रहीम नाम के किसी शख्स से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। यादव, इंदौर के जिला चिकित्सालय के 300 बिस्तरों वाले नये भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस भवन के निर्माण में 83.13 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने प्रदेश भर में यूसीसी पर सभी धर्मों, सभी वर्गों और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से संवाद किया तथा 10 लाख से अधिक नागरिकों के सुझाव एकत्र किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों में हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए कानून-कायदे अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा, ''जब हमारा देश एक है, तो अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए? अगर रामचंद्र नामक कोई व्यक्ति एक शादी करता है, तो रहीम नाम के किसी शख्स से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है।''

सरकारी कर्मचारियों की आधिकारिक पहचान निजी जानकारी नहीं हो सकती : सीआईसी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे लोक सेवकों की पहचान को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत निजी जानकारी नहीं माना जा सकता। सीआईसी ने यह फैसला रेलवे को दो अलग-अलग मामलों में यात्रा टिकट परीक्षकों (टीटीई) के नाम और पदनाम सार्वजनिक करने का निर्देश देते हुए सुनाया।

सूचना आयुक्त स्वागत दास ने उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे के खिलाफ अलग-अलग सुनाए गए फैसलों में कहा कि रेलवे ने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे टीटीई के नाम और पदनाम बताने से इनकार करने के लिए आरटीआई कानून की धारा 8(ए)(जे) के तहत हासिल छूट का गलत इस्तेमाल किया।

इनमें से एक मामला उदयपुर एक्सप्रेस में तैनात एक टीटीई से जुड़ा हुआ था, जिसमें अपील करने वाले ने अधिकारी के नाम और पद के साथ-साथ उनसे जुड़ी शिकायतों, सतर्कता रिकॉर्ड, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा से जुड़ी अन्य जानकारियां मांगी थीं। वहीं, दूसरा मामला असरवा-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से संबंधित था, जिसमें अपीलकर्ता ने ड्यूटी पर तैनात टीटीई का नाम, कर्मचारी आईडी और पदनाम जानना चाहा था। दास ने दोनों ही मामलों में रेलवे की दलीलों को खारिज करते हुए कहा, सार्वजनिक सेवा में अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे किसी लोक सेवक की पहचान उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से जुड़ी जानकारी होती है और इसे आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे) के तहत छूट प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी' नहीं माना जा सकता।

सीआईसी ने कहा कि लोक सेवकों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आरटीआई कानून के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। उसने कहा कि ऐसी बुनियादी जानकारी देने से इनकार करना कानून के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की कमी को बढ़ावा देगा। आयोग ने संबंधित सीपीआईओ को निर्देश दिया कि वे संबंधित टीटीई के नाम और पद से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराएं।

ओवैसी ने मतदाताओं से 20 जुलाई तक एसआईआर फॉर्म जमा करने की अपील की

हैदराबाद/भाषा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लोगों से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के तहत गणना प्रपत्र अंतिम तिथि से काफी पहले जमा करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया नागरिकता से जुड़ी हुई है। ओवैसी ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एआईएमआईएम ने हैदराबाद के मुस्लिम युवा की मदद से एक ऐप तैयार किया है, जिसे मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया में सहायता देने के लिए बनाया गया है।

उन्होंने कहा, ''...हम आपकी मदद कर रहे हैं, ताकि आपके लिए एसआईआर प्रपत्र भरना आसान हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया नागरिकता से जुड़ी हुई है।''

कडपा में डालमिया भारत के सीमेंट संयंत्र की आधारशिला रखी गई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कडपा/भाषा। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने बुधवार को डालमिया भारत कंपनी के 3,100 करोड़ रुपये से प्रस्तावित दूसरे सीमेंट विनिर्माण संयंत्र की यहां आधारशिला रखी। कंपनी का यह नया संयंत्र हरित सीमेंट उत्पादन के लिए तैयार किया जा रहा है और इसके 2027-28 की तीसरी तिमाही तक चालू होने की उम्मीद है। यह दक्षिण भारत में डालमिया भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विनिर्माण इकाई होगी, जिसकी क्लिंकर क्षमता 61 लाख टन प्रतिवर्ष और सीमेंट उत्पादन क्षमता 96 लाख टन सालाना की होगी।

इस अवसर पर लोकेश ने कहा, डालमिया भारत आंध्र प्रदेश के लिए एक मजबूत साझेदार है, जो टिकाऊ औद्योगिकीकरण के जरिये वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के निर्माण के दृष्टिकोण को साझा करती है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश हरित प्रौद्योगिकी आधारित विकास का वैश्विक मानक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बयान के मुताबिक, यह संयंत्र 80 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित होगा और इससे करीब 1,000 रोजगार सृजित होंगे।

शिंदे ने परिसीमन का समर्थन किया, बेहतर शासन और विकास के लिए जरूरी बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को परिसीमन का समर्थन करते हुए कहा कि उक्त प्रक्रिया बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों को न्याय दिलाने और विकास का लाभ उन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए जरूरी है। शिंदे ने भरोसा जताया कि संसद के आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाएंगे।

शिंदे ने हाल में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) छोड़ उनके नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने वाले छह सांसदों के साथ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी अब 20-25 लाख हो गई है, जिससे सांसदों के लिए विकास संबंधी जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। शिंदे ने कहा, परिसीमन जरूरी है, ताकि बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिल सके और विकास का लाभ उन तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए शिवसेना प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस विधेयक को पेश करने का साहस दिखाया है, जो लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद के पिछले सत्र में इस विधेयक को रोका था, लेकिन अब सभी दलों को आगामी सत्र में इसका समर्थन करना चाहिए। 2029 में संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक किए जाने के प्रावधान वाला संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। इस विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। शाह के साथ मुलाकात के बारे में शिंदे ने कहा कि बातचीत उन निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों पर केंद्रित थी, जिनका प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद शिवसेना (उबाठा) छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे। इनमें मराठवाड़ा में सिंचाई परियोजनाओं, रेलवे और सड़क अवसंरचना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और अन्य लंबित प्रस्ताव शामिल हैं।

मलप्पुरम में मूंगफली गले में फंसने से तीन वर्षीय बच्चे की मौत

मलप्पुरम/भाषा। केरल के मलप्पुरम जिले में तीन वर्षीय एक बच्चे के गले में मूंगफली फंस जाने से दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार को कुन्नुमपुरम इलाके में हुई। वेंगारा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, बच्चा घर पर नमकीन खा रहा था। इसी दौरान उसमें मौजूद एक मूंगफली उसके गले में फंस गई जिससे उसका दम घुटने लगा। पुलिस ने बताया कि बच्चे को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सक उसे बचा नहीं सके।

सरकार के खिलाफ नारेबाजी राजद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं : उच्च न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचित लोकतंत्र में सरकार या शासन के किसी भी सांविधिक निकाय के खिलाफ नारेबाजी करना नागरिकों पर राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा कि सरकार के खिलाफ नारे लगाना केवल असहमति व्यक्त करने का एक माध्यम है, न कि नफरत, अवमानना या असंतोष का भाव। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई एक घटना से जुड़े मामले में कैथल के चार निवासियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए की।

उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसक प्रदर्शन दंगा तो हो सकता है, लेकिन इस तरह की हिंसक गतिविधियों को सरकार के खिलाफ घृणा या अवमानना पैदा करने वाले कृत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। कैथल के कलायत थाने में 25 अगस्त, 2017 को दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए (राजद्रोह), 188 (कानूनी आदेश की अवहेलना), 120-बी (आपराधिक साजिश) समेत सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं। पंचकूला की एक अदालत द्वारा गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा में, हरियाणा के कैथल में भीड़ ने बिजली विभाग के दफ़्तर में कथित तौर पर तोड़-फोड़ की।

न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की पीठ ने हरियाणा सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 23 सितंबर, 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 124-ए (राजद्रोह) समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों से बरी कर दिया था।

10वीं उत्तीर्ण करने के बाद आईटीआई पूरा करने वालों को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पणजी/भाषा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को घोषणा की कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दो वर्षीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के समकक्ष माना जाएगा। सावंत ने गोवा बोर्ड समकक्षता प्रमाणपत्र शुरू करने तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बीच मजबूत तालमेल कायम करने समेत आईटीआई शिक्षा में बड़े सुधारों की घोषणा की। इससे उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विद्यार्थियों की संभावनाएं बेहतर होंगी।

मुख्यमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा अब 10वीं के साथ दो वर्षीय आईटीआई पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण वालों के समकक्ष माना जाएगा तथा उन्हें गोवा बोर्ड समकक्षता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आईटीआई और महाविद्यालयों के बीच समन्वय भी स्थापित किया है, ताकि व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकें। सावंत ने कहा, इन सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईटीआई विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विद्यार्थियों के समान शैक्षणिक मान्यता मिले और उनकी रोजगार क्षमता भी बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत को प्रतिभा और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कौशल विकास एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। उन्होंने कहा कि 'स्किल इंडिया मिशन', प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जैसी पहल युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान कर रही हैं तथा उन्हें रोजगार के उभरते अवसरों के लिए तैयार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं में अधिक निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा, कौशल और नवाचार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना ''विकसित भारत'' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक है।

बैठक — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गुरुवार को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय ने सचिवालय में केरल के गृहमंत्री रमेश चेन्निथला से मुलाकात की और तमिलनाडु और केरल के बीच मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम संबंधी गतिविधियों के समन्वय के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक के दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के. ए. सेंगोत्तैयान, निषेध एवं उत्पाद शुल्क मंत्री के. विग्नेश, मुख्य सचिव डॉ. एम. साईकुमार (आपातकालीन आयुक्त), गृह एवं निषेध एवं उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के. मणिवासन (आपातकालीन आयुक्त), पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल (आपातकालीन आयुक्त), वरिष्ठ पुलिस एवं सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।

मुलाकात — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने मुलाकात की और उन्हें याचिकाएं सौंपीं। उनके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के थेनी जिला सचिव एमपी रामचंद्रन, जिला कार्यकारी समिति के सदस्य जीएम नागराजन, तमिलनाडु पहाड़ी जन संघ के राज्य अध्यक्ष पी. दिल्लीबाबू, तमिलनाडु किसान संघ के थेनी जिला सचिव डी. कन्नन और विवास्वामी एम. थंगामलाई, आर. लिंगम और मरुथुबंदी भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कामराज की 124वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई अन्य नेताओं ने बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की 124वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, थिरु के कामराज जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और उत्कृष्ठ जन–नेता थे। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र–निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा, समावेशी विकास और वंचितों के कल्याण जैसे क्षेत्रों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है।

वहीं, आर्लेकर ने कहा, कामराज की जयंती के अवसर पर मैं उस दूरदर्शी नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने तमिलनाडु में शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए बड़े बदलाव की नींव रखी। उन्होंने कहा, कामराज की ओर से शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना जैसी अग्रणी पहलों ने लाखों बच्चों को स्कूलों की ओर खींचा और शिक्षा के लिहाज से सबसे पिछड़े समुदायों के लिए भी सीखने का रास्ता खोला। आर्लेकर ने कहा, कामराज ने स्कूल के बुनियादी ढांचे और शिक्षा पद्धतियों में जो सुधार पेश किए, उन्होंने तमिलनाडु में विकास और सामाजिक समानता की मजबूत नींव रखी।

इस मौके पर विजय ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ यहां अन्ना सलाई स्थित कामराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, महान दूरदर्शी, गरीबों के सच्चे साथी और प्रख्यात नेता के कामराज की जयंती पर उनके त्याग

और योगदान को नमन करता हूं। उन्होंने तमिलनाडु के हर गांव में स्कूल स्थापित किए, सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोले और गरीब बच्चों की भूख मिटाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की।

विजय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के अलावा कामराज ने जलाशय और बड़े उद्योग भी स्थापित किए, जिससे कृषि और औद्योगिक विकास के जरिये तमिलनाडु के लोगों का जीवन बदला।

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि आज महान नेता कामराज की जयंती है, जिन्होंने तमिलनाडु के विकास के लिए अथक प्रयास किए।

उन्होंने कहा, कामराज ने तमिलनाडु में बंद पड़े 6,000 से ज्यादा स्कूलों को फिर से खुलवाया और मध्याह्न भोजन, मुफ्त वर्दी तथा पाठ्यपुस्तकों के जरिये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। औद्योगिक विकास और बांधों के निर्माण के लिए किए गए उनके काम से तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे का भी जबरदस्त विकास हुआ।

कामराज की 124वीं जयंती के मौके पर तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) 13 से 19 जुलाई तक विभिन्न श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

टीएनसीसी अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने बताया कि इस दौरान कामराज की शानदार विरासत को नमन करने के साथ–साथ लंजाम थवीर, नेन्जाम निमिर' (भ्रष्टाचार छोड़ो, गर्व से से डटे रहो) नामक भ्रष्टाचार विरोधी जन–आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) महासचिव ईके पलानीस्वामी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने भी कामराज को श्रद्धांजलि दी।

विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को होगी रिलीज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' महीनों तक चली कानूनी लड़ाई, ऑनलाइन लीक और सेंसर बोर्ड के साथ गतिरोध के बाद अब आखिरकार 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म निर्माता ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। फिल्म निर्माता 'केवीएन प्रोडक्शंस' ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर आधिकारिक तौर पर रिलीज की तारीख की घोषणा की। कंपनी ने पोस्ट में कहा, ''आग में

परखा गया। वक्त की भट्टी में गढ़ा गया। इतिहास रचने के लिए बना। जंग जितनी कठिन होगी, जीत का शोर उतना ही गूंजेगा।'' पोस्ट के साथ ही फिल्म के 23 जुलाई को रिलीज किये जाने संबंधी 'हैशटैग' साझा किए गए। बेंगलूरु स्थित केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'जन नायकन' को हाल ही सेंसर बोर्ड ने 'ए' प्रमाणपत्र दिया है। फिल्म का निर्देशन एच. विनोद ने किया है और करीब सात महीने तक चली प्रक्रिया के बाद पिछले सप्ताह इसे प्रमाण–पत्र मिला।

तमिलनाडु फिल्म वितरक संघ के सूत्रों के अनुसार, फिल्म के इस राज्य में करीब 1,000 सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने की संभावना है। फिल्म को प्रमाण–पत्र मिलने में काफी देरी, कानूनी हस्तक्षेप और 'पायरेसी' जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिल्म को पहले नौ जनवरी, 2026 को पोंगल के अवसर पर रिलीज किया जाना था और निर्माताओं ने इसे 19 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को सौंपा था।

रिपोर्ट के अनुसार, जांच समिति की ओर से सुझाए गए बदलावों को लागू करने के बाद फिल्म को शुरू में यू/ए' प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त माना गया था। हालांकि, बाद में समिति के एक सदस्य की आपत्ति के बाद प्रक्रिया रुक गई। सदस्य ने दावा किया था कि फिल्म के कुछ हिस्से जनभावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। छह जनवरी को केवीएन प्रोडक्शंस ने प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देने की मांग को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया।

करीब एक महीने तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद निर्माताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली और फिल्म को पुनरीक्षण समिति के समक्ष पेश करने का फैसला किया। अप्रैल में बिना प्रमाणित फिल्म का हाई डेफिनिशन (एचडी) संस्करण ऑनलाइन लीक होने के बाद विवाद और गहरा गया। मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि पायरेटेड प्रति को ब्लॉक किए जाने से पहले करीब 1.2 करोड़ लोगों ने इसे देखा था। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने लीक मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक स्वतंत्र फिल्म संपादक भी शामिल है, जिसपर आरोप है कि उसने संपादन सुविधा केंद्र से फिल्म की फुटेज हासिल की थी।

यूनियन बैंक का लाभ पहली तिमाही में 27 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 5,641.52 करोड़ रुपये पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/मुंबई/भाषा। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल–जून तिमाही में 27.5 प्रतिशत बढ़कर 5,641.52 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से बेहतर मार्जिन, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और ब्याज आय बढ़ने से बैंक का लाभ बढ़ा है। बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार यह जानकारी दी।

एक साल पहले 2025–26 की इसी तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 4,427.94 करोड़ रुपये रहा था। बैंक की शुद्ध ब्याज आय आलोच्य तिमाही में सालाना आधार पर 1.05 प्रतिशत बढ़कर 27,203 करोड़ हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 26,919 करोड़ रुपये थी। शुद्ध ब्याज मार्जिन में मामूली वृद्धि से ब्याज आय में वृद्धि सीमित रही। शुद्ध ब्याज मार्जिन में सालाना आधार पर 0.04 प्रतिशत और पिछली तिमाही के मुकाबले 0.16 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई और यह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2.80 प्रतिशत रहा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आशीष पांडे ने भरोसा जताया कि ब्याज दरों के बदलते माहौल के बावजूद मार्जिन को और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुरू की गई एफसीएनआर–बी पहल के तहत सितंबर तक लगभग 1.5–2 अरब डॉलर का पूंजी प्रवाह होगा।

कलबुर्गी में पुलिस पर हमला करने वाले फरार कैदी के पैर में लगी गोल, जेल कर्मचारी निलंबित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कलबुर्गी/भाषा। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक फरार कैदी ने बुधवार को उसे पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर कथित रूप से हमला कर दिया हालांकि जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने यह जानकारी दी। कर्नाटक सरकार ने जेल से फरार होने की घटना के बाद लापरवाही के आरोप में संबंधित जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी संतोष ने पुलिसकर्मियों पर उस समय कथित रूप से हमला किया, जब पुलिस ने उसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिससे संतोष के पैर में गोली लगी। इस घटना में दो पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, संतोष समेत तीन कैदी मंगलवार तड़के यहां कलबुर्गी केंद्रीय कारागार के स्नानगृह की ग्रिल कथित रूप से काटकर और सीढ़ी की मदद से फरार हो गए थे। बाकी दो दोषी कैदियों का पता लगाने के लिए विशेष दल गठित किए गए हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संतोष और घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए कलबुर्गी के सरकारी आयुर्विज्ञान संस्थान (जीआईएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने एक बयान में कहा कि कलबुर्गी केंद्रीय कारागार से तीन कैदियों के फरार होने के मामले में लापरवाही और कर्तव्य में चूक के आरोप में संबंधित जेल अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फरार कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप एक कैदी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मंत्री ने बयान में कहा, गृह मंत्री का पद संभालने के बाद से मैंने गृह विभाग के हर प्रभाग की समीक्षा बैठक की है और सभी प्रभागों को मजबूत बनाने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं राज्य की सभी जेलों का निरीक्षण करूंगा और जेल कर्मचारियों की कार्यकुशलता की भी समीक्षा करूंगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जेल सुधार, सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने जैसे उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरगे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, सिर्फ आलोचना करने के लिए मुंह खोले बैठे भाजपा नेताओं को चाहिए कि वे एक बार यह भी सोचें कि उनके शासनकाल में राज्य की जेलों की क्या स्थिति थी।

भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पीआरसी अधिसूचना तुरंत वापस लेने की मांग की

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने बुधवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार की स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) संबंधी अधिसूचना को तुरंत वापस लेने और इस मामले में उचित संवैधानिक हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। पार्टी ने कहा कि इस अधिसूचना से राज्य के हितों, भारत के संघीय ढांचे के सिद्धांतों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य सरकार पात्र नागरिकों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी करेगी, ताकि वे राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम पूरा कर सकें। इसके बाद राज्य के राजस्व विभाग ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) जारी करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए।

दिशा–निर्देशों के मुताबिक, यह प्रमाणपत्र कर्नाटक में स्थायी निवास का प्रमाण होगा। नागरिक स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। भाजपा ने

राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा, कर्नाटक सरकार की ओर से 26 जून, 2026 को स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अधिसूचना राज्य के हितों, संघीय ढांचे के सिद्धांतों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर डाल सकती है। इसलिए हम संविधान के संरक्षक के रूप में आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और उचित निर्देश जारी करें। राज्यपाल से मिलने वाले भाजपा प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता सी नारायणस्वामी, विधान परिषद सदस्य एन. रवि कुमार और सी. टी. रवि सहित अन्य नेता शामिल थे।

राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य मंसूर अली खान ने ली उच्च सदन की सदस्यता की शपथ

बेंगलूरु/नई दिल्ली। राज्यसभा के दो नवनिर्वाचित सदस्यों मंसूर अली खान और रजनीश कुमार अग्रवाल ने बुधवार को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली।

राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने उपसभापति हरिवंश और महासचिव पी. सी. मोदी की मौजूदगी में दोनों सदस्यों को शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता खान कर्नाटक से निर्वाचित हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अग्रवाल मध्य प्रदेश से चुने गए हैं। खान ने अंग्रेजी में और अग्रवाल ने हिंदी में शपथ ली।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हुईं

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बुधवार के दिल्ली दौरे से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि वह कांग्रेस आलाकमान के साथ अपने मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। उनकी यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मंत्रिमंडल में शामिल होने के इच्छुक नेता जोर–शोर से लामबंदी कर रहे हैं। मीडिया को साझा किए गए आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, शिवकुमार बुधवार शाम राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। शिवकुमार रात में दिल्ली में ही ठहर सकते हैं, जबकि उनकी वापसी फिलहाल निर्धारित नहीं है। हालांकि, उनके दौरे की योजना में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पार्टी सूत्रों का मानना है कि वह नेतृत्व से बातचीत करेंगे।

शिवकुमार ने सोमवार को कहा था कि जब कांग्रेस आलाकमान उन्हें मिलने का समय देगा, तब वह दिल्ली जाएंगे। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था, ''जब भी वे (पार्टी के शीर्ष नेता) मुझे समय देंगे, मैं जाऊंगा। वे मुझे अगले तीन या चार दिन में कोई तारीख देंगे। जैसे ही वह तारीख देंगे, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा।'' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सोमवार को कहा था कि वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद उनसे बातचीत की जायेगी और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र किया जाएगा। दिल्ली रवाना होने से पहले, शिवकुमार ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या से मुलाकात की।

सिद्दरामय्या के बेटे एवं मंत्री यतींद्र सिद्दरामय्या ने मैसूरु में पत्रकारों से कहा , हम इसे (मंत्रिमंडल विस्तार को) जल्द से जल्द करना चाहते हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे
शुद्धि पत्र संख्या 1
सं. SnT-BKN-2026-27-11 दि. 14.07.2026
कार्य का नामः बीकानेर मंडल के रतनगढ़– बीकानेर सेक्शन (34 नग) मे पीएसआर हटाने के लिए संकेत एवं दूर संचार से संबंधित कार्य। शुद्धि पत्र द्वारा निविदा संख्या एस.एण्ड.टी/बी.के.एन/ईटी 294 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते है। **क्रसं.1 संशोधन का विवरणः** कार्य का नाम व स्थान; **निविदा सूचना के अनुसारः** बीकानेर मंडल के रतनगढ़–बीकानेर सेक्शन (34 नग) मे पीएसआर हटाने के लिए संकेत एवं दूर संचार से संबंधित कार्य; **शुद्धि पत्र के अनुसार संशोधनः** बीकानेर मंडल के सादुलपुर–बीकानेर सेक्शन (34 नग) मे पीएसआर हटाने के लिए संकेत एवं दूर संचार से संबंधित कार्य। **नोटः**– अन्य शर्ते यथावत रहेगी।
मण्डल रेल प्रबन्धक (एसएंडटी)
1020-AM/26

दक्षिण पश्चिम रेलवे
निविदा सूचना संख्या / अधिसूचना संख्या
एसडब्ल्यूआर-आरएसपी-एलसी-112-आरओबी-09
दिनांकः 08-07-2026
भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न लिखित कार्यों के लिए ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

कार्य का विवरण	अनुमानित मूल्य
कामसमुद्रम एवं बिसानट्टम स्टेशनों के मध्य कि.मी. 273/100–200 पर एलसी 112 के स्थान पर 1*42 मीटर कंपोजिट गर्डर (रेलवे स्पैन) + कामसमुद्रम सिटी साइड पर +11*18.71 मीटर पीएससी गर्डर + अप्पेनहल्ली पर 5*18.71 मीटर पीएससी गर्डर + 1*5.5*2.5 मीटर के एलएचएस तथा अन्य संबद्ध कार्यों सहित आरओबी का निर्माण (कंपोजिट कार्य)।	Rs. 23,46,81,645/-

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। : 30-07-2026 को 15.00 बजे तक
अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in
उप मुख्य अभियंता /आरओबी
PUB/290/AAZ/PRB/SWR/2026-27
आसान टिकट बुकिंग, पीएनआर स्थिति एवं अन्य रेलवे सेवाओं के लिए रेलवन ऐप डाउनलोड करें।
South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRAILWAYHQ | sw_railways

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Tamil Nadu
(Established by an Act of Parliament, 2009)
Neelakudi, Thiruvarur Tamil Nadu
டெண்டர் அறிவிப்பு / निविदा सूचना / Tender Notice
Hiring of Vehicles for Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur.

டெண்டர் குறிப்பு எண் / निविदा संदर्भ सं./ Tender Ref. No.:	இறுதி தேதி & நேரம் / अंतिम तिथि एवं समय / Last date & Time:
CUTN/PUR/2026-27/04	Please see the CUTN website https://cutn.ac.in/tenders

குறிப்பு / टिप्पणी / Note: மேலும் விவரங்களுக்கு www.cutn.ac.in மற்றும் CPP போர்டல் பார்க்கவும்.
अधिक जानकारी के लिए www.cutn.ac.in और सीपीपी पोर्टल देखें।
For more details, visit www.cutn.ac.in and CPP portal.
-sd-
CBC 21299/11/0004/2627 பதிவாளர் /कुलसचिव/REGISTRAR

नेता हंगामे से नहीं, तर्कपूर्ण बहस और गंभीर चर्चा से बनते हैं : ओम बिरला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। विधानमंडल को राजनीतिक नेतृत्व की प्रशिक्षणशाला बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को जनप्रतिनिधियों से संसदीय परंपराओं का सम्मान करने तथा सार्थक बहस, अध्ययन और रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि सदन में हंगामा करने से नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित तर्कपूर्ण बहस और गंभीर चर्चा से नेता तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने संसदीय परंपराएं राजस्थान विधानसभा से ही सीखी हैं और इसी सदन ने उन्हें विधायी मूल्यों की सीख दी, जो आज तक उनके सार्वजनिक जीवन का मार्गदर्शन कर रही है।

बिरला ने कहा, विधानमंडलों में दिए गए भाषण और हुई बहसें इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं और वर्षों तक उनका अध्ययन किया जाता है। कोई सदस्य जितना अधिक सुनेगा और अध्ययन करेगा, वह उतना ही बेहतर योगदान दे सकेगा। उन्होंने कहा कि विधानमंडल लोकतांत्रिक विमर्श का ऐसा मंच है, जहां सरकार पूरे राज्य के लोगों की अपेक्षाओं, समस्याओं, आलोचनाओं और चुनौतियों को समझ सकती है। उन्होंने कहा, यदि सरकार सदन में उठाए गए मुद्दों का गंभीरता से अध्ययन करे तो समस्याओं की जड़ तक पहुंचकर उनके प्रभावी समाधान तलाशे जा सकते हैं।

बिरला ने राजस्थान विधानसभा को विधायी मूल्यों की पाठशाला बताते हुए कहा कि यह जनप्रतिनिधियों के पूरे राजनीतिक जीवन का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखती है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सटीक और स्पष्ट उत्तर दें। उन्होंने कहा कि विधानसभा और संसद ऐसे मंच हैं, जहां से राज्य और देश के नेतृत्व का निर्माण होता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, जनता जवाबदेह और पारदर्शी शासन चाहती है। जो सरकारें और जनप्रतिनिधि इन मूल्यों का पालन करेंगे, वही सफल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनसेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता राज्य सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा ने ऐतिहासिक कानून बनाकर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नवाचार के जरिए देश की अग्रणी विधान संस्थाओं में अपनी पहचान बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम लोकतंत्र और जनसेवा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा की कार्यवाही से हर पीढ़ी सीखती है। सदन में ऐसी बहस और विचार होने चाहिए, जो राजस्थान के विकास में योगदान दें और आने वाली पीढ़ियों द्वारा भी याद किए जाएं।

उन्होंने कहा कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों के आचरण, समर्पण और कार्यशैली पर लगातार नजर रखती है। इसलिए सभी विधायकों को आत्ममंथन करते हुए जनता के विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा वह संस्था है, जहां जनता के कल्याण के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायकों की भूमिका कमजोर हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में कई विधेयक पर्याप्त चर्चा के बिना और हंगामे के बीच पारित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी विधायकों को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। जूली ने विधानसभा की बैठकों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की।

उन्होंने कहा, हमें विधानसभा को और मजबूत बनाना होगा। जब विधानसभा अपने 100 वर्ष पूरे करे, तब बैठकों की संख्या और सार्थक बहस के मामले में यह, देश में प्रथम स्थान पर हो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र विचारों की सतत बहने वाली गंगा है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के विकास पर केंद्रित होने का अवसर देते हैं। देवनानी ने कहा, लोकतंत्र विचारों की निरंतर बहने वाली गंगा है। ऐसे कार्यक्रम अधिक होने चाहिए। जब हम इस तरह एक मंच पर आते हैं तो राजनीतिक मतभेद पीछे छूट जाते हैं और राजस्थान का विकास हमारा साझा एजेंडा बन जाता है।

उन्होंने बताया कि विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष समारोह का उद्देश्य लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, संवाद को प्रोत्साहित करना और राज्य के विकास के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में वर्तमान और पूर्व विधायक भी उपस्थित थे।

बीकानेर के सरकारी अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। बीकानेर के सरकारी प्रिंस बिजय सिंह मेमोरियल (पीबीएम) अस्पताल में ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव होने के बाद एक महीने से अधिक समय तक इलाज कराने वाली 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हाल के समय में इस अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव के बाद मौत की यह तीसरी घटना है, जिसके साथ ही पिछले तीन महीने में राजस्थान में प्रसूताओं की मौत का आंकड़ा 19 हो गया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घिया ने बताया कि कमला मेघवाल नामक महिला को आठ जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि महिला को मधुमेह था और यह उसकी तीसरी गर्भावस्था थी। डॉ. घिया ने कहा, चिकित्सकों की एक टीम ने उसका इलाज किया। एक समय उसकी हालत में सुधार भी हुआ था लेकिन बाद में अचानक उसकी हालत बिगड़ गई और मेडिकल टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा, हमारी टीम ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो सके। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में प्रसव के बाद जिन छह महिलाओं की हालत बिगड़ी थी उनमें से तीन की मौत हो गई है, जबकि बाकी तीन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

मेघवाल से पहले इसी अस्पताल में प्रसव के बाद ऐसी ही दिक्कतों के कारण कुछ हफ्ते पहले दो अन्य महिलाओं की मौत हुई थी। 19 जून को बीकानेर में प्रसव के बाद दिक्कतों का सामना करने वाली छह महिलाओं में से 20 साल की प्रीति की सबसे पहले मौत हुई थी। दो दिन बाद 26 साल की शारदा की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि तीनों महिलाओं को ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर पेशाब आना बंद हो गया था।

पिछले तीन महीने में राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के 19 मामलों में से कोटा में पांच, बीकानेर में तीन, जोधपुर में दो और भीलवाड़ा व बांसवाड़ा में नौ मामले दर्ज किए गए हैं। पीबीएम अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेघवाल को प्रसव के दिन ही भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जच्चा-बच्चा दोनों ठीक थे, लेकिन चूंकि महिला को मधुमेह था और पहले भी दो बार ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव हो चुका था इसलिए चिकित्सकों ने इस बार भी ऑपरेशन से प्रसव का सुझाव दिया और यह प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई थी। उन्होंने कहा कि हालांकि, अगले ही दिन यानी नौ जून को उसे कुछ दिक्कतें हुईं और उसे डायलिसिस पर रखा गया। अधिकारी ने बताया कि महिला की हालत में कुछ समय के लिए सुधार हुआ और 'वेंटिलेटर सपोर्ट' हटा लिया गया।

उन्होंने कहा कि इसके बाद उसके 'सी-सेक्शन' के टांकों से जुड़ी एक और सर्जरी हुई लेकिन कई अंगों के काम करना बंद करने की वजह से महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस बीच, पीबीएम अस्पताल में जान गंवाने वाली मेघवाल के परिजनों और कई संगठनों के सदस्यों ने बुधवार को मुर्दाघर के बाहर प्रदर्शन किया। महिला के रिश्तेदार बुधवार सुबह से ही मुर्दाघर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक मेघवाल को न्याय नहीं मिलता, यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। महिला के पति ने भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सकों ने सही जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि मेघवाल का अस्पताल की गहन उपचार इकाई (आईसीयू) में लगभग एक महीने तक इलाज किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री ने बांसवाड़ा जिला अस्पताल का दौरा किया

जयपुर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बुधवार को बांसवाड़ा जिला अस्पताल का दौरा किया और चार महिलाओं की मौत के मामले में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि जिन चार महिलाओं की मौत हुई है, उनमें से एक महिला पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि मामले में जांच जारी है और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खींवसर ने बाद में अस्पताल के प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थिएटर और मातृत्व वार्ड का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सभी मेडिकल रिकॉर्ड एकत्र कर लिए गए हैं और उनकी जयपुर में अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के चिकित्सक मौजूद रहे।

एसएमएस अस्पताल में कटे जननांग को सर्जरी से ठीक किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल (एसएमएस) में डॉक्टरों ने धारदार हथियार के हमले में एक युवक के लगभग पूरी तरह कट गए जननांग को जटिल सर्जरी के जरिए ठीक किया गया। करीब 40 दिन के उपचार के बाद युवक की हालत अब सामान्य है। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, 29 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उसका जननांग लगभग पूरी तरह कट गया था। घटना के करीब चार घंटे के भीतर उसे एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां प्लास्टिक सर्जरी एवं पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विभाग की टीम ने उसी रात आपातकालीन सर्जरी की।

यह जटिल ऑपरेशन प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार जैन के मार्गदर्शन में इकाई प्रमुख डॉ. संगीता ठाकुरानी की टीम ने किया जिसमें डॉ. मुकुल धाभाई, डॉ. नवप्रीत और डॉ. ईशिता गौर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अस्पताल के अनुसार, सर्जरी के दौरान क्षतिग्रस्त मूत्रमार्ग, स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा की सूक्ष्म स्तर पर मरम्मत की गई। ऑपरेशन के बाद लगातार निगरानी और विशेषज्ञ उपचार के कारण अंग की कार्यक्षमता सुरक्षित रही। करीब 40 दिनों के इलाज के बाद मरीज सामान्य रूप से मूत्र त्याग करने में सक्षम हो गया।

डॉ. राकेश कुमार जैन ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी केवल सौंदर्य बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं, औद्योगिक हादसों, अंग कटने, जलने की चोटों, कैंसर के बाद अंगों के पुनर्निर्माण और जन्मजात विकृतियों के उपचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन शरीर के पुनर्निर्माण के साथ मरीज का आत्मविश्वास और सम्मान भी वापस लाने का काम करते हैं।

डॉ. संगीता ठाकुरानी ने कहा कि ऐसे मामलों में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि मरीज को चोट लगने के कुछ घंटों के भीतर अस्पताल पहुंचाने से उपचार सफल हो सका। उन्होंने लोगों से अपील की कि गंभीर चोट, अंग कटने या दुर्घटना की स्थिति में तत्काल विशेषज्ञ अस्पताल पहुंचें, क्योंकि समय पर उपचार से कई बार ऐसे अंगों को भी बचाया जा सकता है जिन्हें खोया हुआ मान लिया जाता है।

सरकार ने 18 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 18 अधिकारियों के तबादले किए हैं जिनमें महानिदेशक (डीजी) रैंक के दो अधिकारी भी शामिल हैं। कार्मिक विभाग ने मंगलवार देर रात इस बारे में आदेश जारी किया। इसके तहत जोधपुर में नया पुलिस आयुक्त और अजमेर व भरतपुर में नए महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त किए गए, साथ ही चार जिलों में नए पुलिस अधीक्षक तैनात किए गए।

आदेश के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण व यातायात) अनिल पालीवाल को महानिदेशक व कमांडेंट जनरल (गृह रक्षा) के पद पर नियुक्त किया गया। इस पद पर काम कर रहीं मालिनी अग्रवाल को महानिदेशक (यातायात) के पद पर लगाया गया है। जोधपुर के पुलिस आयुक्त शरत कविराज को महानिरीक्षक (अपराध) नियुक्त किया गया, जबकि विशेष शाखा (एसएसबी) के महानिरीक्षक अंशुमन भोमिया जोधपुर के नए पुलिस आयुक्त होंगे।

महानिरीक्षक (आयोजना) डॉ. रवि को पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज नियुक्त किया गया। उन्होंने राजेंद्र सिंह की जगह ली है जिन्हें पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक (सतर्कता) के पद पर भेजा गया। भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई का तबादला महानिरीक्षक (आयोजना) के पद पर किया गया जबकि महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) प्रीति चंद्रा को भरतपुर रेंज का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। सरकार ने इस फेरबदल के तहत जोधपुर ग्रामीण, हनुमानगढ़, बालोतरा और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के तबादले भी किए हैं।

गैंगस्टर रोहित गोदारा का पुश्तैनी मकान रातों-रात ढहाया गया, पुलिस ने जांच शुरू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। बीकानेर में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के पुश्तैनी मकान का बड़ा हिस्सा कथित तौर पर अज्ञात लोगों ने रातों-रात ढहा दिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार लूनकरनसर कस्बे के पास स्थित मकान में तोड़-फोड़ की घटना के वक्त कोई मौजूद नहीं था। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।

लूनकरनसर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) रणवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को मंगलवार सुबह इस घटना की जानकारी मिली जिसके बाद स्थानीय थाना प्रभारी ने मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि इमारत के बड़े हिस्से को ढहाने के लिए 'अर्थमूवर मशीन' (भारी मशीन) का इस्तेमाल किया गया था।

सिंह ने बताया कि आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस तोड़-फोड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इलाके में घर एक-दूसरे से काफी दूर-दूर बने हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निवासियों का मानना है कि घरों में चल रहे एयर कूलर के शोर के कारण मशीन की आवाज शायद किसी को सुनाई नहीं दी होगी।

पुलिस ने कहा कि घटना का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध सबूतों की जांच की जा रही है। इस मकान में पहले गोदारा के पिता संत दास, मां गीता, भाई हनुमान स्वामी और हनुमान की पत्नी व बच्चे रहते थे। हालांकि तोड़-फोड़ के समय उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि गोदारा के माता-पिता और भाई फिलहाल जबरन वसूली के अलग-अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

हनुमान स्वामी को गंगानगर में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था जबकि उनके माता-पिता पर चुरू के रतनगढ़ में दर्ज एक अलग मामले में आरोप हैं। पुलिस ने बताया कि गोदारा खुद गिरफ्तारी से बच रहा है और माना जा रहा है कि वह अभी अजरबैजान में है। अधिकारियों के अनुसार हनुमान की पत्नी 10-12 दिन पहले अपने बच्चों के साथ इस घर से चली गई थी और पड़ोसियों से खेतों की देखभाल करने का अनुरोध किया था। सिंह ने कहा कि तोड़-फोड़ के संबंध में अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पिछले हफ्ते ऑपरेशन हार्डबॉल के सिलसिले में गोदारा का नाम सामने आया था। यह अभियान अमेरिका, कनाडा और यूरोप की प्रवर्तन एजेंसियों ने 'भारतीय संगठित अपराध नेटवर्क' के खिलाफ मिलकर चलाया था। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, इस अभियान में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या समेत कई अपराधों से जुड़े 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक गोदारा की पहचान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अपराध नेटवर्क के यूरोप मुखिया के तौर पर की गई है।

राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना

जयपुर। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून का असर कमजोर होने के बीच राज्य में कई जगह आने वाले दिनों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। इसके अनुसार, आगामी कुछ दिनों में राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में 3040 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज धूलभरी हवाएं चल सकती हैं।

बुधवार सुबह तक बीते चौबीस घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। राज्य के पश्चिमी भाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस अवधि में सबसे अधिक 18.0 मिलीमीटर बारिश अलवर में दर्ज की गई। सर्वाधिक 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान गंगानगर में और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया।

ब्रिक्स उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठकों के लिए सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करें : श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आगामी 6 एवं 7 अगस्त को जयपुर में आयोजित होने वाली ब्रिक्स उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठकों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं तय समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करें, ताकि आयोजन का सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन हो सके। बुधवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों का विभागवार जायजा लिया तथा आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात तथा इंडोनेशिया शामिल हैं। राजस्थान में आयोजित होने जा रही यह बैठक राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, जिसके लिए विभिन्न देशों के मंत्री एवं वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल जयपुर आएंगे। मुख्य सचिव ने गृह विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को एयरपोर्ट, आयोजन स्थल, होटल तथा अन्य निर्धारित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक प्रतिनिधिमंडलों के निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन के लिए प्रभावी मोटरकेड एवं यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा।

शराबबंदी का नियम तोड़ने पर युवक को बरगद के पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के सायरा थाना क्षेत्र के कमोल गांव में शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने पर तथाकथित पंचों ने एक युवक को तालिबानी सजा दे डाली। पंचों ने युवक का पैर रस्सी से बांधकर उसे बरगद के पेड़ से उल्टा लटकाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके साथ ही पीड़ित पर 11 हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी ठोक दिया। यह खौफनाक वारदात करीब दो महीने पहले 12 मई 2026 को घटित हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। नशे में पिता से अभद्र व्यवहार करने का था आरोपसायरा थानाधिकारी कानाराम सीरवी ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया- कमोल गांव के पंचों ने अपने स्तर पर गांव और भील बस्ती में शराबबंदी लागू कर रखी थी।

11 मई की रात को पीड़ित युवक चूनाराम गमेती ने कथित तौर पर शराब पी और नशे की हालत में अपने घर पहुंचा। घर पर जब उसके पिता ने उसे टोका, तो चूनाराम ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उस पर पिता के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा। अगले दिन यानी 12 मई को समाज के कुछ पंचों ने इस मामले को लेकर भील बस्ती में एक बैठक (पंचायत) बुलाई। पंचायत में शराबबंदी का नियम तोड़ने और पिता से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में चूनाराम पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पंचों का गुस्सा सिर्फ जुर्माने पर शांत नहीं हुआ। सजा के नाम पर उन्होंने कानून हाथ में लेते हुए चूनाराम का एक पैर मजबूत रस्सी से बांधा और उसे सबके सामने बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका दिया। उल्टा लटकाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसी दौरान भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी बर्बरता का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो मंगलवार (14 जुलाई) को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीबी जी राम जी योजना से सशक्त होंगे गांव, साकार होगा विकसित भारत का संकल्प

जयपुर,। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांवों के विकास से ही देश एवं प्रदेश का विकास होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रारम्भ की गई वीबी जी राम जी योजना विकसित भारत 2047 की मजबूत आधारशिला बनेगी तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी के साथ ही गांवों में बुनियादी विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वीबी जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश के ग्रामीण विकास का समग्र ब्लूप्रिंट तैयार करें। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने वाले स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।मैपिंग एवं रिकॉर्ड संधारण से सुनिश्चित हो पारदर्शिता- बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में वीबी जी राम जी योजना क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

युवा आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य की बड़ी युवा आबादी कोई चुनौती नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को कौशल देकर जनसंख्या को आर्थिक विकास की शक्ति में बदल रही है।

विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस वर्ष यूनेस्को की थीम साझा भविष्य के लिए कौशल है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि सभी लोगों को समान अवसर मिलें। आदित्यनाथ ने कहा, देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश को दुनिया की सबसे बड़ी युवा कार्यशक्ति होने पर गर्व है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतनी बड़ी आबादी चुनौती है या नहीं। यह हमारी ताकत है। हम युवाओं को कौशल देकर इस जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करेंगे और उन्हें समृद्धि की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। उन्होंने पिछली सरकारों, खासकर समाजवादी पार्टी (एसपी), पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई थी, कौशल विकास की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी और युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा, उस समय असुरक्षा का माहौल था। न महिलाएं सुरक्षित थीं, न व्यापारी। युवाओं की पहचान का संकट था। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर नहीं थे और राज्य के लोगों को बाहर अपनी पहचान के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का नाम लिए बिना उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों पर एक परिवार का कब्जा था और भर्ती में भ्रष्टाचार होता था।

उन्होंने कहा, अगर भर्तियां निकलती थीं तो 'चाचा-भतीजे की जोड़ी' पैसे वसूलने निकल पड़ती थी। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपजाऊ जमीन, भरपूर जल संसाधन और बड़े धार्मिक स्थलों के बावजूद उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहा गया। उन्होंने कहा, प्रकृति ने हमें गंगा, यमुना, गोमती, राप्ती, नारायणी और सरयू जैसी नदियां दी हैं। हमारे पास अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, मनकामेश्वर धाम, शाकंभरी धाम और महाकुंभ जैसे धार्मिक स्थल हैं।

बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज के कई नेता भाजपा में शामिल हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को झटका देते हुए पिछले वर्ष पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कई नेता बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर के.सी. सिन्हा और कुम्हरार व दीघा विधानसभा क्षेत्रों से जन सुराज के उम्मीदवार रहे क्रमशः रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पिछले साल विधानसभा चुनाव में मनेर सीट से जन सुराज के उम्मीदवार रहे गोपाल सिंह तथा पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर सिन्हा भी भाजपा में शामिल हुए। बांकीपुर में 30 जुलाई को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से है।

भाजपा में शामिल होने वाले संजय सरावगी ने पटना में कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा की नीतियों से प्रेरित होकर पूरे देश में विपक्षी दलों के नेताओं के भाजपा में शामिल होने की होड़ लगी है। देशभर से लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल हुए सभी लोग लगातार संगठन के लिए काम करेंगे, जिससे भाजपा और मजबूत होगी। प्रोफेसर के.सी. सिन्हा ने कहा कि वह शिक्षा के माध्यम से भारत को फिर से ''सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने'' के उद्देश्य से भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात के बीच केंद्र सरकार को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भारत की आवाज पूरी दुनिया में और बुलंद हो सके। पूरा विश्व उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहा है। भारत पहले भी विश्वगुरु रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से उस गौरव को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। रितेश रंजन सिंह ने कहा कि वह ''भावनाओं में बहकर'' जन सुराज में चले गए थे, जिसके लिए वह क्षमा चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी को भी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए।

मंत्रिमंडल ने एक करोड़ टन नई यूरिया क्षमता सृजित करने के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य देश में एक करोड़ टन अतिरिक्त यूरिया उत्पादन क्षमता सृजित करना और सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले इस उर्वरक के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर नए निवेश ढांचे के तहत प्राकृतिक गैस आधारित आठ से नौ नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, पिछले एक दशक में छह नए संयंत्र स्थापित होने से यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता कम हुई है। आठ से नौ नए संयंत्रों की स्थापना से देश अपनी पूरी आवश्यकता की पूर्ति घरेलू स्तर पर कर सकेगा और इस उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि यूरिया की मांग हर साल लगभग पांच प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत में यूरिया का उत्पादन लगभग तीन करोड़ टन है जबकि मांग चार करोड़ टन है। एक करोड़ टन की कमी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। आज मंजूर की गई नीति का उद्देश्य अतिरिक्त यूरिया उत्पादन क्षमता सृजित करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। वैष्णव ने कहा कि इस नीति के तीन प्रमुख स्तंभ -सब्सिडी की गणना के लिए स्थिर एवं परिवर्तनीय लागत को अलग करना, यूरिया संयंत्र संचालित करने वाली कंपनियों के लिए 12-16 प्रतिशत के बीच सुनिश्चित प्रतिफल और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करना है। उन्होंने कहा कि नई नीति, नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 का विस्तार है। भारत की घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता वर्तमान में करीब 2.69 करोड़ टन है जबकि यूरिया का आयात करीब एक करोड़ टन है।

यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने 11 दिन में दाखिल किया आरोप-पत्र

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के 11 दिन के भीतर ही आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह मामला एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने एक व्यक्ति पर शादी का झूठा वादा करके उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी आसिफ उर्फ हनी को इस मामले में एक महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। जनकपुरी थाने में बीएनएस की धारा 69 (कपटपूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके यौन उत्पीड़न), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपना धर्म छिपाया और शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप के अनुसार, आरोपी ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया, उसके साथ मारपीट की और उसकी निजी तस्वीरें एवं वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। प्राथमिकता के आधार पर जांच की गयी। अधिकारियों ने कहा कि सबूतों से संकेत मिला है कि दोनों लगातार संपर्क में थे और जांच के एक पहलू के तौर पर आरोपी के कार्यस्थल से उपस्थिति रिकॉर्ड एकत्र किए गए।

राष्ट्रपति मुर्मू ने आयुर्वेद विद्यार्थियों से आचार्य सुश्रुत के मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद के युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से आचार्य सुश्रुत द्वारा दिखाये गये मार्ग का अनुसरण करने और चिकित्सा में नैतिकता तथा रोगियों के प्रति करुणामय सेवा के अपने संकल्प पर अडिग रहने का बुधवार को आग्रह किया। मुर्म ने साथ ही पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की वैश्विक स्वीकृति को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों को अपनाने की भी अपील की। सुश्रुत जयंती के मौके पर यहां अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में आयोजित तीन दिवसीय 'अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम् 2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि आयुर्वेद का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है। उन्होंने विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को ईमानदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यावहारिक शोध करने तथा उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करने की सलाह दी।

मुर्मू ने कहा, ''जहां भी उचित हो, उन्हें नई तकनीकों का इस्तेमाल करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।'' उन्होंने उनसे आचार्य सुश्रुत द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने और चिकित्सा में नैतिकता तथा रोगियों के प्रति करुणामय सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान एआईआईए की एमआरआई इकाई का भी उद्घाटन किया। मुर्मू ने आयुर्वेद जगत को आचार्य सुश्रुत की जयंती पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सदियों पहले आचार्य सुश्रुत ने जब शल्य चिकित्सा पद्धति का सूत्रपात किया था, तब वह अपने समय की एक क्रांति से कम नहीं था। राष्ट्रपति ने कहा कि आचार्य सुश्रुत अनेक जटिल एवं नवाचारपूर्ण शल्य क्रियाओं के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं।

सोनम वांगचुक के अनशन की अनदेखी कर सरकार क्रूरता कर रही : अभिजीत दीपके

नई दिल्ली/भाषा। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बुधवार को अपनी भूख हड़ताल के 18वें दिन भी लगातार चिकित्सकीय निगरानी में हैं। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत नहीं करने को लेकर ''सरकार को क्रूर'' बताया। कॉजपा का मेडिकल की 'प्रवेश परीक्षा नीट' में कथित अनियमितताओं के विरोध में जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन बुधवार को 26वें दिन में प्रवेश कर गया। कॉजपा की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, वांगचुक अभी भी ''बहुत कमजोर'' हैं और लगातार चिकित्सकीय निगरानी में हैं। वांगचुक का वजन घटकर 57.15 किलोग्राम रह गया है। पिछले 24 घंटे में उनका वजन 400 ग्राम कम हुआ है।

भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से अब तक उनका कुल वजन 8.9 किलोग्राम कम हो चुका है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, उनका रक्तचाप 105/76, रक्त शर्करा का स्तर 80 एमजी/डीएल और ऑक्सीजन संतृप्ति 97 प्रतिशत दर्ज की गई। शरीर में पानी का स्तर संतोषजनक बताया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि वह होश में हैं और मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क हैं, लेकिन उन्हें लगातार निगरानी की आवश्यकता है। दीपके ने लिखा, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 18वां दिन है। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के लिए न्याय की मांग को लेकर अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया, उसे सरकार की ओर से केवल चुप्पी मिली है। सरकार न केवल जवाबदेही से बच रही है, बल्कि वह क्रूर भी है।

ममता गुट बिड़ला तारामंडल के सामने कर सकती है रैली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को बिड़ला तारामंडल के पास 21 जुलाई को 'शहीद दिवस' रैली आयोजित करने की अनुमति दे। टीएमसी कई वर्षों से मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड में विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली आयोजित करती आ रही है। उच्च न्यायालय ने विक्टोरिया हाउस के सामने से रैली का स्थान बदलकर बिड़ला तारामंडल के पास करने का आदेश मुख्य रूप से यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और कानून-व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से दिया।

अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि वह टीएमसी के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली बिड़ला तारामंडल के सामने वाली सड़क पर आयोजित करने की अनुमति दे। कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में शहीद दिवस की दो अन्य रैलियां भी प्रस्तावित होने का उल्लेख करते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करें। इलाके में एक रैली कांग्रेस की और दूसरी टीएमसी के प्रतिद्वंद्वी गुट की आयोजित होने वाली है।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को बिड़ला तारामंडल के सामने सड़क के एक हिस्से पर रैली आयोजित करने की अनुमति दे, जबकि सड़क के दूसरे हिस्से को वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रखा जाए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पार्टी को यह प्रयास करना चाहिए कि रैली में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 2,500 तक सीमित रहे। कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया गया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाए, क्योंकि उसी दिन तीन अलग-अलग स्थानों पर तीन रैलियां आयोजित की जाएंगी।

अदालत ने निर्देश दिया कि यह रैली 21 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शाम 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) को 20 कार्यकर्ताओं के नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालत के आदेश का पालन हो। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नीत टीएमसी की ओर से एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने रैली आयोजित करने के अनुरोध को मंजूरी देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे उत्तर और मध्य कोलकाता को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो सकता है। शहीद दिवस रैली की अनुमति के लिए याचिका पेश करते हुए गुट के वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह रैली दो या तीन साल को छोड़कर 1993 से ममता बनर्जी के नेतृत्व में मध्य कोलकाता में विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित की जाती रही है।

केंद्र ने वाराणसी के लिए दो राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी, 25,500 करोड़ रुपये होगा निवेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वाराणसी के लिए दो राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर लगभग 25,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए वरुणा नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.22 किलोमीटर लंबे लिंक रोड के विकास को मंजूरी दी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना में मुख्य सड़क मार्ग, फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड समेत छह/चार-लेन वाला मुख्य रूप से एलिवेटेड गलियारा शामिल है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) के तहत कुल 10,998.32 करोड़ रुपये की लागत से पूरा करेगा। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली रूपरेखा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से देश में ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह गलियारा वाराणसी में भीड़ कम करने की योजना का एक अहम हिस्सा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच बिना रुकावट के संपर्क सुविधा देगा। साथ ही, इससे वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी हवाईअड्डा, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रामनगर पोर्ट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के घाटों और पास के चंदौली इलाके तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। बयान में कहा गया है कि 80-100 किमी/घंटा की गति के लिए डिजाइन की गयी इस परियोजना से राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा। यानी इसमें लगभग 50 प्रतिशत की कमी आएगी। बयान में आगे कहा गया है कि इससे शहर के सड़क नेटवर्क पर भीड़ कम होगी, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, गाड़ियों को चलाने का खर्च कम होगा और यात्रियों तथा माल की आवाजाही तेज और बिना रुकावट के हो सकेगी। यह परियोजना एक आर्थिक केंद्र (चंदौली सामाजिक आर्थिक क्षेत्र), एक सामाजिक केंद्र (चंदौली) और छह बड़े लॉजिस्टिक केंद्रों तक पहुंच बेहतर बनाकर क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगी। इससे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मल्टीमॉडल' एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि सीसीईए ने वाराणसी शहर में भीड़ कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच एक गलियारा बनाने को भी मंजूरी दी है। यह गलियारा गंगा नदी के तट से जुड़ा होगा। बयान के अनुसार, 46.04 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में छह-लेन वाला एलिवेटेड मुख्य मार्ग, 'केबल-स्टेयड' पुल, 'फुट-ओवर ब्रिज'-के साथ बड़ा पुल, लूप, रैंप, लिंक रोड और सर्विस रोड शामिल हैं।

असम में गरीबी कम करने में प्रत्यक्ष नकद अंतरण की अहम भूमिका : मुख्यमंत्री हिमंत

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य में गरीबी कम करने में प्रत्यक्ष नकद लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की बहुआयामी गरीबी दर को घटाकर एकल अंक (10% से कम) पर लाना है। विधानसभा में राज्य बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए शर्मा ने बताया कि असम में बहुआयामी गरीबी दर 2015 के 32.67% से घटकर अब 14.47% रह गई है। राज्य में गरीबी उन्मूलन में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हमारा लक्ष्य इसे (बहुआयामी गरीबी दर) घटाकर एकल अंक तक लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि गरीबी पर सीधे प्रहार करना है तो डीबीटी सबसे प्रभावी माध्यम है। राज्य में विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार से मिले सहयोग के कारण उनकी सरकार व्यापक और परिवर्तनकारी विकास कार्य करने में सफल रही है। शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकारें गरीबी कम करने में इसलिए सफल नहीं हो सकीं क्योंकि उस समय लोगों के पास न तो बैंक खाते थे और न ही आधार की सुविधा उपलब्ध थी।

पवार का शिंदे के कार्यालय में जाना महज संयोग, राजनीतिक मुलाकातों में साजिश का कोण न निकालें : सुले

मुंबई/भाषा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की बारामती से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने पार्टी प्रमुख शरद पवार द्वारा पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दफ्तर में अपने विधायकों के साथ की गई बैठक को लेकर लगाई जा रही अकटलों को बुधवार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह घटना महज 'एक संयोग' थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बैठकों को शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए और लोगों से अपील की कि वे यह सोचना बंद करें कि राजनीतिक नेताओं के बीच होने वाली हर बैठक किसी साजिश का हिस्सा होती है। पवार ने गत बुधवार (आठ जुलाई को) को मुंबई में विधान भवन परिसर में शिंदे के कार्यालय में अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की थी।

वरिष्ठ नेता पवार लंबे समय से लंबित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार समिति के सदस्य के तौर पर एक बैठक में शामिल होने के लिए विधानसभा परिसर गए थे। राकांपा(शप) अध्यक्ष ने बैठक के बाद शिंदे से उनके चैंबर में जाकर मुलाकात की। राकांपा(शप)विपक्षी गठबंधन 'महा विकास अघाडी' (एमवीए) का हिस्सा है। इस बैठक से राजनीतिक अटकलें शुरू हो गईं और राकांपा (शप) की सहयोगी शिवसेना (उबाठा)ने भी इसकी आलोचना करते हुए इसे गद्दारों को महिमामंडित करने वाला कदम बताया। उद्धव ठाकरे नीत पार्टी ने यह टिप्पणी शिंदे और उनकी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए की थी। सुले ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने पवार से आराम करने को कहा था, इसके बावजूद वह विधानसभा परिसर में गए।

मथुरा विवाद : उच्चतम न्यायालय ने हिंदू पक्षों के बीच चर्चा होने के बीच सुनवाई टाली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यह सूचित किये जाने पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टाल दी कि विभिन्न हिंदू पक्ष इस बात पर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इस मामले में किसका मुकदमा मुख्य मामला होगा।

उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2025 के एक आदेश को चुनौती देने वाले एक हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय ने अन्य वाद में एक हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना था। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त नियत की। ऐसा तब किया गया जब हिंदू पक्षों में से एक के वकील ने बताया कि वादियों के बीच कुछ अनौपचारिक बातचीत चल रही है। आरंभ में खंडपीठ ने कुछ हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन तथा इस विवाद में एक अन्य हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील पीवी योगेश्वरन से पूछा कि क्या उनके बीच कोई बातचीत चल रही है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, अगर दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत चल रही है, तो हम मामले की सुनवाई टाल देंगे। योगेश्वरन ने पीठ से कहा कि वे नहीं चाहते कि अदालत बातचीत के बारे में आदेश में कुछ भी दर्ज करे, क्योंकि यह वादियों के बीच हो रही थी और 'अनौपचारिक' है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि मामले को कई बार स्थगित किया जा चुका है और इस बार इसे तभी स्थगित किया जा सकता है जब पक्षों के बीच कोई बात चल रही हो। पीठ ने वकीलों से कहा, ''हम पक्षों को बातचीत के लिए बाध्य नहीं करने जा रहे हैं। अगर कुछ चल रहा है, तो उसे आदेश में भी दर्ज किया जा सकता है। इसमें क्या हर्ज है?'' पीठ ने यह कहते हुए मामले को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। उच्चतम न्यायालय पहले से ही मस्जिद समिति और हिंदू पक्षों की कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें 26 मई 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मथुरा की अदालत में लंबित विवाद से जुड़े सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी शामिल है।

सुविचार

अच्छे विचारों से मन सुंदर बनता है, अच्छे कर्मों से जीवन। दूसरों की सहायता करें, मुस्कान बांटें, खुशियाँ बढ़ती जाएँगी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सुविधाओं के शत्रु

रेलवे के कई यात्रियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में एसी कोच से करोड़ों रुपए की चद्दर, कंबल, तकिया कवर आदि पार करने की घटनाएं शर्मनाक हैं। इन कोचों में यात्रा करने वाले लोगों के बारे में यह तर्क भी नहीं दिया जा सकता कि वे दैनिक जीवन में आर्थिक तंगी और चीजों की किल्लत के कारण ऐसा कर रहे हैं। रेलवे की संपत्ति यात्रियों की सुविधा के लिए है। कई यात्री इसे अपनी निजी संपत्ति समझकर हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता पाया जाए, उससे संबंधित सामान की कीमत का कई गुणा जुर्माना वसूला जाए। रेलवे में उक्त चीजों की चोरी की घटनाओं से पता चलता है कि कई लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। ये जहां भी जाते हैं, अपना 'हुनर' दिखाते हैं। किसी जगह की सुंदरता को कैसे नष्ट करना है, साफ जगह पर कैसे गंदगी फैलानी है, कहीं पर व्यवस्था कैसे बिगाड़नी है – इन सब कार्यों में उन्हें महारत हासिल होती है। पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ बाराती अपने घर लौटते वक्त कन्या पक्ष द्वारा किए गए इंतजाम को तहस-नहस करते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने चद्दर, गद्दे, तकिए आदि को मिलकर फाड़ दिया था। अगर इतनी एकता और बल का प्रदर्शन किसी सकारात्मक काम में करते तो मानवता की बहुत बड़ी सेवा होती। जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती है। वे व्यवस्था बिगाड़ने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।

भारत में अक्सर लोग शिकायतें करते हैं कि 'सरकार हमारे लिए सुविधाओं का निर्माण नहीं करती है ... उसे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता एवं स्वच्छता की परवाह नहीं है।' ये शिकायतें पूरी तरह निराधार नहीं हैं। कई जगह सरकारी प्रयासों में कमियां रहती हैं, लेकिन हर कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। जो लोग एसी कोच से चद्दर, कंबल, तकिया कवर उड़ा रहे हैं, क्या उन्हें सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा है? व्यवस्था बिगाड़ने में लोगों के किरदार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। राजस्थान के जयपुर शहर में सुंदर एवं कई सुविधाओं से युक्त नई बसें चली थीं। लोगों ने एक महीने में ही उनकी सूरत बिगाड़ दी। कहीं गुटखा-पान खाकर थूक दिया, किसी सीट को उधेड़ दिया, कहीं आपत्तिजनक शब्द लिख दिए – ये नजारे विभिन्न शहरों की बसों में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। विद्यार्थी जीवन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। बच्चों को इस बात की शिक्षा देनी चाहिए कि हमें सार्वजनिक स्थानों एवं संसाधनों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसा कोई काम न करें, जिससे इनकी गुणवत्ता और अस्तित्व पर आंच आए। कुछ साल पहले एक स्कूल के बच्चे, जो बड़ी कक्षाओं से थे, राजस्थान के एक शहर में टेबल टेनिस का मैच खेलने गए। वहां उन्हें एक धर्मशाला में ठहराया गया। विद्यार्थियों ने मैच जीतने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। वे हारकर धर्मशाला लौट आए। अचानक एक लड़के को खुराफात सूझी। उसने अपने साथियों को सुझाव दिया कि 'हम मैच हार गए, कोई बात नहीं ... अब इस धर्मशाला के कमरों में लगे बल्ब उतारकर ले चलते हैं।' उन लड़कों को हार की मायूसी सता रही थी। उन्हें ऐसी खुराफात में आनंद का स्रोत नजर आया। उन्होंने योजना के अनुसार कई कमरों के बल्ब उतार लिए। जब वे अपने गांव रवाना हुए तो धर्मशाला के प्रबंधक ने सबको रोक लिया। उसने भारी जुर्माना वसूला और स्कूल को सूचित कर दिया। इस घटना से उनकी बहुत किरकिरी हुई। वास्तव में, ऐसे लोगों को चोरी करने, व्यवस्था बिगाड़ने, किसी जगह की सुंदरता नष्ट करने में आनंद का स्रोत नज़र आता है। जिस दिन उन्हें अहसास हो जाएगा कि 'गलत हरकतें महंगी पड़ेंगी', वे इनसे तौबा कर लेंगे।

ट्वीटर टॉक

ज्ञान से बुद्धि, हुनर से तरक्की और अच्छी सेहत से हर संकल्प पूरा होता है। आज हमारे युवा इन्हीं गुणों को अपना रहे हैं, जिससे देश की पहचान और भी मज़बूत हो रही है। धन का सबसे बड़ा रूप हुनर है; दौलत में सबसे बड़ा है सीखना।

–नरेन्द्र मोदी

यह ऐतिहासिक इंडिया-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की आर्थिक ताकत, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और बढ़ती ताकत का एक मज़बूत सबूत है। इस एग्रीमेंट के ज़रिए, इंडियन प्रोडक्टस को णघ मार्केट में बड़े पैमाने पर एक्सेस मिलेगा, एक्सपोर्ट को नई तेज़ी मिलेगी।

–दिया कुमारी

विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह सदन सिर्फ़ एक इमारत नहीं है; यह राजस्थान के लाखों लोगों की उम्मीदों और उनकी लोकतांत्रिक आस्था का मंदिर है। यहां जनहित में 400 से ज़्यादा बिल पास हुए हैं।

–अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

नारी सशक्तीकरण

डॉ. अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं को संपत्ति, विवाह, शिक्षा के मामलों में कोई स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने बहुत सोच-विचार कर 'हिंदू कोड बिल' तैयार किया। इस बिल में उन्होंने प्रावधान रखे थे कि बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार हो, महिलाओं को तलाक का कानूनी अधिकार मिले एवं बहुविवाह समाप्त होकर एक पत्नी नियम लागू हो। उन्होंने जब इस बिल को संसद में प्रस्तुत किया तो अनेक कट्टरपंथियों ने इसका जमकर विरोध किया। विरोधियों का कहना था कि यह बिल भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देगा। डॉ. अंबेडकर लगभग चार सालों तक बिल को पारित कराने के लिए प्रयास करते रहे। कालांतर में उन्होंने वर्ष 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि, 'मैं अपने पद पर बने रहने के बजाय महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना और इस्तीफा देना बेहतर समझता हूं।' आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। बाद में उनके सिद्धातों पर गौर कर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम जैसे कानून बने।

सामयिक

क्या भारत विरोध ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट में धकेला?

महेन्द्र तिवारी
मोबाइल : 9989703240

दक्षिण एशिया की स्थिरता केवल भारत और पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है तो निवेश बढ़ सकता है, व्यापारिक मार्ग खुल सकते हैं, ऊर्जा सहयोग को गति मिल सकती है और करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि अविश्वास और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है तो विकास की संभावनाएं सीमित ही रहेंगी।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह का हालिया बयान दक्षिण एशिया की राजनीति में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अंधे विरोध की नीति न अपनाता और भारत के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ता, तो आज पाकिस्तान को कर्ज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध होते तो पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता का वातावरण बनता। किसी वरिष्ठ पाकिस्तानी नेता की ओर से इस प्रकार का आत्मविश्लेषण असामान्य माना जा रहा है क्योंकि दशकों से पाकिस्तान की राजनीतिक और सामरिक सोच का बड़ा हिस्सा भारत विरोध पर आधारित रहा है। राणा सनाउल्लाह ने अपने बयान में वर्ष 2015 का उल्लेख किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंचे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उस समय इसे दोनों देशों के संबंधों में नई शुरुआत की संभावना के रूप में देखा गया था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद पठानकोट आतंकी हमला हुआ और उसके बाद दोनों देशों के संबंध फिर से तनावपूर्ण हो गए। राणा सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान उस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा और इसके लिए स्वयं पाकिस्तान की राजनीतिक सोच तथा भारत विरोधी दृष्टिकोण जिम्मेदार रहा।

भारत और पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास विभाजन के समय से ही जटिल रहा है। दोनों देशों ने अनेक युद्ध देखे, सीमा पर लगातार तनाव बना रहा और आतंकवाद के मुद्दे ने विश्वास की कमी को और गहरा किया। कश्मीर विवाद ने भी संबंधों को सामान्य होने नहीं दिया। समय समय पर शांति वार्ताएं हुईं, व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए गए और सांस्कृतिक आदान प्रदान की पहल भी हुई, लेकिन हर बार कोई न कोई घटना संबंधों को पीछे धकेल देती रही। इस पृष्ठभूमि में किसी पाकिस्तानी वरिष्ठ नेता द्वारा यह स्वीकार करना कि अवसर गंवाया गया, अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, बढ़ता राजकोषीय घाटा, महंगाई, ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बार बार सहायता लेने की मजबूरी ने उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। अनेक विशेषज्ञ लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि यदि दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग बढ़े और भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार सामान्य हो, तो दोनों देशों को लाभ मिल सकता है। भारत विशाल बाजार है और पाकिस्तान की कई वस्तुओं के लिए निकटतम व्यापारिक साझेदार भी हो सकता है। इसी संदर्भ में राणा सनाउल्लाह का बयान आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत ने पिछले एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, डिजिटल भुगतान प्रणाली, विनिर्माण और वैश्विक कूटनीति में उल्लेखनीय विस्तार किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान आर्थिक संकटों, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से जूझता रहा है। यदि दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापारिक संबंध होते तो सीमा पार व्यापार, परिवहन, ऊर्जा सहयोग और निवेश के नए अवसर विकसित हो सकते थे। दक्षिण एशिया विश्व की सबसे कम आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों में गिना जाता है। इसका एक बड़ा कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध भी हैं। राणा सनाउल्लाह ने यह भी संकेत दिया कि आज पाकिस्तान भारत से संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल संपर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि वर्तमान परिस्थितियों में विश्वास की कमी बहुत अधिक है और पहले की तुलना में संवाद स्थापित करना कहीं अधिक कठिन हो गया है।

भारत का दृष्टिकोण भी पिछले कुछ वर्षों में अधिक स्पष्ट और कठोर हुआ है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। भारत का आधिकारिक रुख यह है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद समाप्त नहीं होता, तब तक संबंधों का सामान्य होना कठिन है। इसी कारण व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद भी सीमित रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई तनावपूर्ण घटनाओं ने इस दूरी को और बढ़ाया है। राणा सनाउल्लाह का बयान केवल भारत की प्रशंसा भर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर भी टिप्पणी माना जा रहा है। पाकिस्तान में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि राष्ट्रीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं पर खर्च होता है जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाते। यदि क्षेत्रीय तनाव कम हो तो संसाधनों का बेहतर उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकता है। इस दृष्टि से उनका बयान पाकिस्तान के भीतर चल रही व्यापक बहस को भी सामने लाता है।

दक्षिण एशिया विश्व की लगभग एक चौथाई आबादी का घर है, लेकिन आर्थिक सहयोग के मामले में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंध स्थापित हों तो क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, जल प्रबंधन, परिवहन और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत, भाषाई समानता और ऐतिहासिक संबंध भी सहयोग को मजबूत आधार दे सकते हैं। यही कारण है कि समय समय पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती रही हैं। हालांकि केवल राजनीतिक इच्छा पर्याप्त नहीं होती। दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम आवश्यक हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना, आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई, मानवीय मुद्दों का समाधान, मछुआरों और कैदियों की रिहाई, व्यापारिक प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाना ऐसे उपाय हो सकते हैं जो धीरे धीरे विश्वास का वातावरण तैयार करें। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी क्योंकि दोनों देशों के बीच कई दशकों का अविश्वास मौजूद है।

राणा सनाउल्लाह के बयान पर पाकिस्तान के भीतर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इसे यथार्थवादी स्वीकारोक्ति बताया, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाजी माना। भारत में भी इस बयान को सावधानी के साथ देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सकारात्मक परिवर्तन का आकलन केवल बयानों से नहीं बल्कि व्यवहारिक कदमों से किया जाना चाहिए। जब तक दोनों देशों की नीतियों में ठोस बदलाव दिखाई नहीं देता, तब तक ऐसे वक्तव्यों को संभावनाओं के संकेत के रूप में ही देखा जाएगा। इतिहास यह बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार सकारात्मक पहल हुई है। बस सेवा शुरू हुई, व्यापार बढ़ाने की कोशिश हुई, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ा।

लेकिन हर बार किसी बड़ी सुरक्षा घटना ने इन प्रयासों को झटका दिया। इसलिए भविष्य में यदि कोई नई शुरुआत होती है तो उसे अधिक मजबूत संस्थागत आधार और पारस्परिक विश्वास की आवश्यकता होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि राणा सनाउल्लाह का बयान पाकिस्तान सरकार की किसी नई आधिकारिक नीति की घोषणा नहीं है। यह एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता का सार्वजनिक आकलन है, जिसे व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फिर भी यह इस बात का संकेत अवश्य देता है कि पाकिस्तान के भीतर कुछ राजनीतिक वर्ग अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि लगातार टकराव की नीति से अपेक्षित लाभ नहीं मिला और आर्थिक विकास के लिए पड़ोसी देशों के साथ सहयोग आवश्यक हो सकता है।

दक्षिण एशिया की स्थिरता केवल भारत और पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है तो निवेश बढ़ सकता है, व्यापारिक मार्ग खुल सकते हैं, ऊर्जा सहयोग को गति मिल सकती है और करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि अविश्वास और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है तो विकास की संभावनाएं सीमित ही रहेंगी। राणा सनाउल्लाह का वक्तव्य इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह अतीत की नीतियों पर आत्मचिंतन का संकेत भी है और भविष्य की संभावनाओं की ओर इशारा भी। हालांकि वास्तविक परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं बल्कि ठोस नीतिगत निर्णयों, विश्वास निर्माण के उपायों और निरंतर संवाद से ही संभव होगा। यदि दोनों देश अपने मतभेदों को नियंत्रित करते हुए साझा हितों पर आगे बढ़ने का रास्ता खोजते हैं, तो न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरा दक्षिण एशिया अधिक शांत, समृद्ध और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ सकता है।

नजरिया

न्याय की भाषा अंग्रेज़ी, पीड़ित की भाषा हिंदी

प्रो. आरके जैन अरिजीत

सुप्रीम कोर्ट का हालिया प्रश्न – क्या अंग्रेज़ी को भारत की स्वदेशी भाषा माना जा सकता है?-सिर्फ न्यायालय का सवाल नहीं, भारत की भाषाई चेतना पर दस्तक है। यह बहस अंग्रेज़ी के पक्ष-विपक्ष की नहीं, उस मानसिकता की है जिसने आज़ादी के आठ दशक बाद भी भाषा को आत्मसम्मान नहीं, हैसियत का पैमाना बना रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आई अंग्रेज़ी आज विश्वविद्यालयों, न्यायालयों, प्रशासन, विज्ञान, तकनीक और कॉरपोरेट जगत की प्रमुख भाषा है। करोड़ों भारतीय इसे शिक्षा और रोज़गार का माध्यम बना चुके हैं, इसलिए इसे पूरी तरह विदेशी कहना यथार्थ से मुंह मोड़ना होगा। पर क्या लंबे उपयोग से कोई भाषा स्वदेशी हो जाती है? यदि हाँ, तो स्वदेशी का आधार इतिहास होगा, संस्कृति या सुविधा? सुप्रीम कोर्ट ने भाषा नहीं, भारतीय आत्मविश्वास का प्रश्न उठाया है। वही आत्मविश्वास जिसने कभी संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, असमिया और सैकड़ों बोलियों के बल पर विश्व को ज्ञान दिया, लेकिन आज अपने ही देश में स्वयं को सिद्ध करने के लिए विदेशी भाषा का सहारा खोजता है। इस प्रश्न का सबसे बड़ा कटघरा हमारी न्याय व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अधिकांश उच्च न्यायालयों की कार्यवाही व निर्णय आज भी अंग्रेज़ी में होते हैं। विडंबना यह है कि न्याय उसी नागरिक के लिए लिखा जाता है, जो उसकी भाषा नहीं समझता। स्वयं न्यायालय भी मान चुका है कि फैसलों और आदेशों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद आवश्यक है, क्योंकि न्याय तभी सार्थक है, जब वह जनता की भाषा में पहुंचे। फिर भी अदालतों में अंग्रेज़ी का प्रभुत्व निर्विवाद है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यदि जनता की भाषा से दूर रहेगा, तो न्याय और नागरिक के बीच दूरी बनी रहेगी। क्या केवल वर्षों के प्रयोग से अंग्रेज़ी स्वदेशी हो जाएगी, या न्याय व्यवस्था को भारतीय भाषाओं से जोड़ना ही लोकतांत्रिक सुधार होगा? यह प्रश्न केवल भाषा का नहीं, न्याय तक समान पहुंच का है।

आज का सबसे कठोर सत्य यह है कि अंग्रेज़ी भारत में केवल भाषा नहीं, वर्गीय शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। यही भाषा कुछ के लिए अवसरों का द्वार है, तो लाखों के लिए अदृश्य दीवार। महंगे विद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक संस्थाएं इसे योग्यता की पहली शर्त मानती हैं। वहीं गांव का प्रतिभाशाली विद्यार्थी, दलित-बहुजन युवा और मातृभाषा में शिक्षित लाखों छात्र क्षमता नहीं, भाषा की बाधा से पीछे छूट जाते हैं। तीन-भाषा नीति पर वर्षों से जारी बहस और दक्षिण भारत का प्रतिरोध इसी भाषाई वर्चस्व की आशंका का संकेत है। यदि अंग्रेज़ी को स्वदेशी मान लेने से यह असमानता और गहरी होती है, तो क्या हम नई गुलामी को ही वैधता नहीं दे रहे? कभी सत्ता तलवार से चलती थी, आज भाषा के प्रमाणपत्र से चलती है। इतिहास इस बहस का सबसे ईमानदार साक्षी है। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने स्पष्ट लिखा था कि उसका उद्देश्य ऐसे भारतीय तैयार करना है, जो रक्त और रंग से भारतीय, लेकिन विचार, नैतिकता, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज़ हों। यह केवल शिक्षा नीति नहीं, मानसिक उपनिवेश की योजना थी। स्वतंत्र भारत ने राजनीतिक आज़ादी तो पा ली, पर भाषाई स्वाधीनता का संघर्ष अधूरा रह गया। समय के साथ अंग्रेज़ी का स्वरूप भी बदला है। आज हिंग्लिश, तम्लिश, बेंग्लिश जैसी मिश्रित भाषाएं बताती हैं कि भारत हर भाषा को अपना रंग दे सकता है। अंग्रेज़ी भी अब भारतीय अनुभवों से समृद्ध है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह बदलाव हमारी 22 अनुसूचित भाषाओं और सैकड़ों बोलियों की कीमत पर हो रहा है? यदि नई पीढ़ी मातृभाषा से पहले अंग्रेज़ी में सोचने लगे, तो यह केवल भाषा का नहीं, सांस्कृतिक स्मृति के क्षरण का संकेत होगा।

दुनिया का अनुभव भारत को स्पष्ट संकेत देता है। जापान ने जापानी, जर्मनी ने जर्मन, फ्रांस ने फ्रांसीसी, चीन ने मंदारिन और इज़राइल ने पुनर्जीवित हिब्रू के बल पर ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्रीय पहचान को सशक्त बनाया। इन देशों ने अंग्रेज़ी सीखी, उसका उपयोग किया, लेकिन उसे अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया। भारत का मार्ग टकराव नहीं, संतुलन का होना चाहिए। नई शिक्षा नीति मातृभाषा आधारित शिक्षा पर बल देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद, भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि की पढ़ाई और बहुभाषी डिजिटल ज्ञान-संसाधन बताते हैं कि ज्ञान अब अंग्रेज़ी की कैद में नहीं है। फिर अंग्रेज़ी को स्वदेशी घोषित करने की जल्दबाज़ी क्यों? असली चुनौती अंग्रेज़ी को हटाना नहीं, भारतीय भाषाओं को उस स्तर तक पहुंचाना है, जहाँ किसी विद्यार्थी का भविष्य उसकी भाषा नहीं, प्रतिभा तय करे। यहीं सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न सबसे अधिक दूरदर्शी बन जाता है। यह हिंदी बनाम अंग्रेज़ी, उत्तर बनाम दक्षिण या किसी भाषा की श्रेष्ठता का विवाद नहीं, उस भारत की खोज है जहाँ हर बच्चा मातृभाषा में सोच सके, क्षेत्रीय भाषा से समाज से जुड़े और अंग्रेज़ी के माध्यम से दुनिया से संवाद करे। यही बहुभाषिक भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि अंग्रेज़ी को स्वदेशी कहकर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई, तो लोकगीत, लोककथाएं, दर्शन, लोकविज्ञान, क्षेत्रीय साहित्य और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक स्मृतियां हाशिए पर चली जाएंगी। लेकिन यदि अंग्रेज़ी वैश्विक अवसरों की भाषा और भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय जीवन की आत्मा बनें, तो वे प्रतिद्वंद्वी नहीं, परस्पर सहयोगी होंगी। भाषा का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, सह-अस्तित्व सुरक्षित करेगा।

दरअसल, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि स्वदेशी का अर्थ केवल उत्पत्ति से है। भारत का इतिहास बताता है कि उसने अनेक संस्कृतियों, विचारों और भाषाओं को अपनाया, पर अपनी आत्मा कभी नहीं खोई। इसलिए न अंग्रेज़ी का विरोध समाधान है, न महिमामंडन। असली प्रश्न यह है कि निर्णय, ज्ञान और आने वाली पीढ़ी के सपनों की भाषा कौन होगी। यदि प्रशासन, न्याय, विज्ञान, चिकित्सा, शोध और तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, तो अंग्रेज़ी कभी चुनौती नहीं बनेगी। लेकिन यदि भारतीय भाषाएं घर, कविता और उत्सव तक सिमट गईं, और अंग्रेज़ी सत्ता, ज्ञान व अवसर की भाषा बन गई, तो वही मानसिक असमानता लौटेगी, जिसकी नींव औपनिवेशिक शासन ने रखी थी। गुलामी केवल विदेशी शासन से नहीं आती, वह तब भी आती है, जब कोई समाज अपनी भाषा पर विश्वास खो देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भाषाई निर्णय नहीं दिया, बल्कि भारत के सामने एक मूल प्रश्न रख दिया-क्या भाषा केवल सुविधा का माध्यम होगी या राष्ट्रीय आत्मविश्वास का आधार? अंग्रेज़ी वैश्विक अवसरों का द्वार है, लेकिन भारत की सभ्यता, लोकज्ञान, संवेदना और सांस्कृतिक चेतना भारतीय भाषाओं में ही जीवित हैं। इसलिए न अंग्रेज़ी का विरोध समाधान है, न उसे स्वदेशी मानकर भारतीय भाषाओं का विकल्प बनाना। आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है, जहाँ न्याय जनता की भाषा में मिले, शिक्षा मातृभाषा में विकसित हो, तकनीक हर भारतीय भाषा को समान अवसर दे और अंग्रेज़ी दुनिया से संवाद का सेतु बने, प्रभुत्व का नहीं। अंततः यह बहस अंग्रेज़ी की नहीं, भारत के भाषाई आत्मविश्वास की है। जो राष्ट्र अपनी भाषाओं को सम्मान देता है, वही अपने ज्ञान, संस्कृति और भविष्य को भी सुरक्षित रखता है। भारत की वास्तविक भाषाई स्वतंत्रता अंग्रेज़ी को स्वदेशी सिद्ध करने में नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय जीवन का स्वाभाविक आधार बनाने में है।

महत्त्वपूर्ण
Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law. Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ब्रिटेन में 16-17 वर्ष के किशोरों के लिए स्वैच्छिक रात्रिकालीन सोशल मीडिया कर्फ्यू की योजना

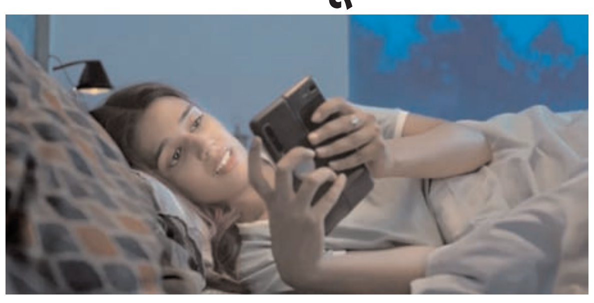

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लंदन/एपी। ब्रिटिश सरकार ने 16 और 17 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के लिए रात के समय स्वैच्छिक सोशल मीडिया कर्फ्यू लागू करने की योजना की बुधवार को घोषणा की। इसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन होने के नुकसान से बचाना है। सरकार ने कहा कि लंबे समय तक उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन से जोड़े रखने वाली सुविधाएं, जैसे एक के बाद एक वीडियो अपने-आप चलने (ऑटोप्ले) का विकल्प, भी बड़े किशोरों के लिए अपने आप बंद रहेगा। हालांकि, आलोचकों ने इन उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि किशोर चाहें तो इन डिफॉल्ट सेटिंग' को स्वयं बदल सकेंगे।

यह प्रस्तावित प्रतिबंध सरकार द्वारा एक महीने पहले 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की योजना की घोषणा के बाद आया है। यह प्रतिबंध अगले वर्ष बसंत से स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे मंचों पर लागू होने की संभावना है, जबकि व्हाट्सऐप और सिग्नल जैसी मैसेजिंग सेवाएं इसके दायरे से बाहर रहेंगी। प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर सरकार के कार्यकाल के अंतिम चरण में लाई गई इन योजनाओं को लागू करने के लिए कानून बनाना होगा। माना जा रहा है कि उनके संभावित उत्तराधिकारी एंडी बर्नहैम भी इन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे।

ब्रिटेन के ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री कनिष्क नारायण ने इस आशंका को खारिज किया कि किशोर स्वैच्छिक रूप से सोशल मीडिया कर्फ्यू को नजर अंदाज करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा मानना किशोरों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में 300 से अधिक किशोरों और उनके अभिभावकों पर किए गए एक हालिया पायलट कार्यक्रम में रात के समय सोशल मीडिया के इस्तेमाल में उल्लेखनीय कमी आई। इसके साथ ही प्रतिभागियों की नींद और एकाग्रता में भी सुधार देखा गया।

उन्होंने 'स्काई न्यूज' से कहा, ''अक्टूबर में कुछ मंचों ने इस तरह की डिफॉल्ट सेटिंग लागू की थीं। 90 प्रतिशत से अधिक किशोरों ने हमें बताया कि उन्होंने इन सेटिंग को बरकरार रखा है। इसलिए उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट हैं और इस पहल का उद्देश्य भी स्पष्ट है।'' ब्रिटेन की प्रमुख बाल अधिकार संस्था 'एनएसपीसीसी' ने कहा कि ये प्रस्ताव युवाओं के सोशल मीडिया अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं, लेकिन अकेले ये पर्याप्त नहीं होंगे। इंग्लैंड की बाल आयुक्त रेचल डी सूजा ने इस पहल को ''सकारात्मक कदम'' बताया। उन्होंने कहा कि युवा सोशल मीडिया का उपयोग कम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसमें कठिनाई होती है। उन्होंने कहा, ''मैं यह जानना चाहती हूं कि कर्फ्यू जैसी नीतियों को किस तरह लागू किया जाएगा । मैं यह सुनिश्चित करने के लिए इन पर करीबी नजर रखूंगी कि वे प्रभावी साबित हों।''

उच्चतम न्यायालय में अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार विधि छात्रों को जेल भेजा गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और सुरक्षाकर्मी से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार दो विधि छात्रों को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों छात्रों को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दिल्ली पुलिस का 14 दिन की न्यायिक हिरासत का अनुरोध स्वीकार करते हुए 24 वर्षीय प्रबल प्रताप और 23 वर्षीय चंदर भान को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि दोनों को 29 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

प्रबल प्रताप उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है और लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष का छात्र है। वह इस मामले में स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में अदालत में पेश हुआ था। वहीं, चंदर भान उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का रहने वाला है और विधि पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष का छात्र है। दोनों को 10 जुलाई को हुई घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना उच्चतम न्यायालय में 'प्रबल प्रताप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' से संबंधित विशेष अनुमति याचिका (सिविल) की सुनवाई के दौरान हुई थी। पुलिस के अनुसार, प्रबल प्रताप ने सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अदालत कक्ष के अंदर कागज फेंके और हंगामा किया, जिससे कार्यवाही बाधित हुई।

पुलिस के अनुसार, जब एक सुरक्षाकर्मी ने प्रबल प्रताप को रोकने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर उनके साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें अपनी सरकारी ड्यूटी करने से रोकने का प्रयास किया। इस मामले में तिलक मार्ग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जागरूकता

मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार को मध्य प्रदेश पुलिस के 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान की शुरुआत के लिए आयोजित एक नशा विरोधी जागरूकता रैली के दौरान प्रतिभागियों का नेतृत्व करता एक रोबोट।

रानी मुखर्जी को मिलेगी मानद डॉक्टरेट

मुंबई/एजेन्सी

हिंदी सिनेमा की दमदार अभिनेत्रियों में शुमार रानी मुखर्जी ने अपने तीन दशक लंबे फिल्मी करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि समाज के कई अहम मुद्दों को भी उठाए। अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित ला ट्रोब यूनिवर्सिटी उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित करेगी। यह सम्मान उन्हें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) 2026 के दौरान दिया जाएगा। इस उपलब्धि पर रानी ने कहा कि सिनेमा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक रहा है और इसी ने उन्हें जीवन को अलग-अलग नजरिए से समझना सिखाया। रानी मुखर्जी ने इस सम्मान पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ''ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। सिनेमा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक रहा है।

मैंने हमेशा माना है कि अच्छी कहानियां लोगों के भीतर संवेदनाएं जगाने, जरूरी विषयों पर बातचीत शुरू करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखती हैं।'' रानी मुखर्जी को यह मानद उपाधि 14 अगस्त 2026 को मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा होगा। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों के लिए उनके लंबे समय से किए जा रहे सामाजिक कार्यों को भी मान्यता देता है।

अपने सम्मान को लेकर रानी मुखर्जी ने कहा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न लंबे समय से दुनिया के सामने भारतीय सिनेमा की बेहतरीन तस्वीर पेश करता रहा है। ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर यह सम्मान मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ला ट्रोब यूनिवर्सिटी और आईएफएफएम की पूरी टीम की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। यह मेरे लिए बेहद यादगार पल है। रानी ने अपने फिल्मी सफर को याद करते हुए कहा, ''मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे ऐसे किरदार निभाने का अवसर मिला, जिनके जरिए मैं संघर्ष, हिम्मत, जुनून और उम्मीद जैसी भावनाओं को पर्दे पर दिखा सकीं। इंसानी कहानियां हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती रही हैं।

हर किरदार ने मुझे कुछ नया सिखाया। ऑस्ट्रेलिया और आईएफएफएम से मिला यह सम्मान मैं अपने देश भारत और दुनिया भर के उन सभी लोगों को समर्पित करती हूं, जिनके प्यार और भरोसे ने मुझे एक अभिनेत्री के रूप में आगे बढ़ने की ताकत दी। दर्शकों के प्यार ने ही मेरी जिंदगी को इतना समृद्ध बनाया है।''

फिल्म 'जन नायकन' 23 को होगी रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। इसे विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। रिलीज डेट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच उत्साह साफ देखा जा सकता है। फिल्म के निर्माताओं ने घोषणा की है कि 'जन नायकन' 23 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म विजय के अभिनय करियर को एक यादगार विदाई देगी। विजय ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ में ही नहीं, बल्कि पूरे देश-विदेश में भी है। यही वजह है कि 'जन नायकन' साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है, जबकि इसका निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। मेकर्स का दावा है कि फिल्म में दमदार कहानी, बड़े स्तर का निर्माण और शानदार सिनेमाई अनुभव देखने को मिलेगा। पूरी टीम फिल्म को विजय के करियर के अनुरूप एक यादगार फिल्म बनाने में जुटी हुई है।

फिल्म निर्माता वेंकट के. नारायण ने रिलीज डेट की घोषणा के साथ खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा, सिनेमा में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं और 'जन नायकन' भी उन्हीं खास पलों में से एक है। थलापति विजय के बड़े पर्दे पर आखिरी बार नजर आने वाली फिल्म का हिस्सा बनना हमारे लिए सम्मान की बात है। हमें खुशी है कि हम यह फिल्म दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसकों तक पहुंचा रहे हैं।

वेंकट के. नारायण ने आगे कहा, विजय का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने एक अभिनेता के रूप में करियर शुरू किया और मेहनत, लोकप्रियता और लोगों से जुड़े रहने के कारण लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। यही भरोसा और प्यार उन्हें राजनीति तक लेकर आया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि जनता के साथ उनका रिश्ता कितना मजबूत है। उन्होंने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि 'जन नायकन' दर्शकों के लिए एक यादगार सिनेमाई अनुभव साबित होगी। यह फिल्म विजय के शानदार फिल्मी करियर को एक भावनात्मक विदाई देगी, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

जमीन विवाद को लेकर युवक पर हमले के आरोप में धीरेन्द्र शास्त्री के भाई गिरफ्तार

छतरपुर (मप्र)/भाषा। छतरपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और गोलीबारी करने के आरोप में बुधवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक दिन पहले मंगलवार को पुलिस ने गर्ग और उसके तीन साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। छतरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि राजनगर थाना क्षेत्र में हुई घटना में गर्ग और अंकित मिश्रा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान अज्ञात आरोपियों के नाम जानने की कोशिश की जा रही है।

पटले ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और गाली-गलौच के आरोप में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद से जुड़ी घटना जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के कोढ़ा गांव में मंगलवार दोपहर हुई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य एकत्र किए और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका शालिग्राम गर्ग से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि वह दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। हमले में घायल मोती कुशवाहा (30) को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि कुशवाहा अपने घर पर था, तभी गर्ग और उसके तीन साथियों ने उसे ललकारा और जब वह घर से बाहर आया तो आरोपियों ने उस पर लाठियों से हमला किया और कथित तौर पर गोलियां भी चलाईं।

पकुशवाहा ने पुलिस को बताया कि एक गोली उसके शरीर को छूते हुए निकल गई। पीड़ित का आरोप है कि वह जुगल किशोर पांडेय नामक व्यक्ति की ओर से गर्ग के खिलाफ जमीन पर कथित कब्जे से जुड़े मामले में गवाही देने वाला था।

प्रचार

नई दिल्ली के 'द ललित' होटल में आगामी पंजाबी रोमांटिक फिल्म इश्कनामा के प्रचार कार्यक्रम के दौरान अभिनेता शहनाज़ गिल और जय रंधावा।

सलमान खान की 'मातृभूमि' की राह हुई लंबी

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पहले इस फिल्म को अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज किए जाने की योजना थी, लेकिन अब इसके इस वर्ष रिलीज होने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म से जुड़े कुछ लंबित मुद्दों के कारण इसकी रिलीज लगातार टल रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म को रिलीज करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन यदि मौजूदा समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो इसे वर्ष 2027 तक टाला जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि यदि विवाद जल्द सुलझ भी जाता है, तब भी उपयुक्त रिलीज डेट मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश प्रमुख तारीखें पहले से बुक हैं। बताया गया है कि सलमान खान किसी अन्य बड़ी फिल्म से बॉक्स ऑफिस टकराव से बचना पसंद करते हैं और इसी वजह से जल्दबाजी में रिलीज का फैसला नहीं लिया जाएगा।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यदि 'मातृभूमि' अगले साल तक टलती है तो 2027 में सलमान खान की दो बड़ी फिल्में रिलीज हो सकती हैं। उनकी दूसरी फिल्म ' एसवीसी63', जिसमें अभिनेत्री नयनतारा भी नजर आएंगी, ईद 2027 के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित बताई जा रही है। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित है। बताया जा रहा है कि फिल्म की विषयवस्तु को लेकर उठी आपत्तियों के कारण इसे अभी तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से अंतिम प्रमाणपत्र नहीं मिल पाया है। ऐसे में फिल्म की रिलीज पर अंतिम फैसला सेंसर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।

'उड़ता तीर' के सेट से सामने आया आयुष्मान-सारा का धमाकेदार डांस

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। इस बीच फिल्म के सेट से एक बिहाइंड द सीन्स (बीटीएस) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दोनों कलाकार रोमांटिक अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद फिल्म को लेकर प्रशंसकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। वायरल वीडियो में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लोकप्रिय गीत 'ऐ काश के हम' की धुन पर रोमांटिक डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सारा सिल्वर रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं, जबकि आयुष्मान नीले रंग के सूट में दिखाई दे रहे हैं। इस क्लिप को देखने के बाद प्रशंसक यह कयास लगा रहे हैं कि क्या यह गीत फिल्म का हिस्सा होगा या सिर्फ शूटिंग का एक अभ्यास दृश्य है।

बताया जा रहा है कि 'उड़ता तीर' एक जासूसी कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें आयुष्मान एक बार फिर अपने चिर-परिचित हास्य अंदाज में दिखाई देंगे। इससे पहले आयुष्मान और सारा की जोड़ी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में नजर आई थी, जिसे दर्शकों ने पसंद किया था। अब दोनों दूसरी बार बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे।

हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने अभी तक रिलीज की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन फिल्म ट्रेड विश्लेषक तरण आदर्श के अनुसार 'उड़ता तीर' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। यदि यह तारीख तय रहती है तो बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर सैफ अली खान और अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'हैवान' से होगी। ऐसे में पहली बार सारा अली खान और उनके पिता सैफ अली खान की फिल्में आमने-सामने नजर आ सकती हैं।

मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए : अंजना सुखानी

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री अंजना सुखानी ने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जॉन अब्राहम और अजय देवगन जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया है। अब वह अपनी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में हैं। इस कड़ी में आईएएनएस के साथ बातचीत में अंजना ने फिल्म, इम्तियाज अली के साथ काम करने के अनुभव, फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव और अपने लंबे सफर को लेकर कई बातें साझा कीं। अंजना सुखानी ने कहा, ''मेरे लिए 'मैं वापस आऊंगा' बेहद खास फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म से इम्तियाज अली का नाम जुड़ा हुआ है। उनके साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। दुनियाभर के कलाकार उनके साथ काम करने का सपना देखते हैं और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे यह मौका मिला। फिल्म की पूरी टीम के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, खासकर नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ के साथ। नसीर साहब के साथ काम करना किसी लाइव मास्टरक्लास जैसा अनुभव है। उन्हें देखकर ही अभिनय की बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं।'' फिल्म में वेदांग रैना और शरवरी के साथ काम करने के अनुभव पर अंजना ने कहा, ''मेरी कहानी फिल्म में अलग समय से जुड़ी हुई है, इसलिए उनके साथ ज्यादा सीन नहीं थे। हालांकि, ट्रेलर लॉन्च और शूटिंग के दौरान कुछ मुलाकातें जरूर हुईं। वेदांग और शरवरी दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हैं। जब मैंने दोनों का पहला सीन देखा तो मैं काफी प्रभावित हुई। वे फिल्म में नई ऊर्जा लेकर आए हैं।''

आज के समय में मॉडल, अभिनेता और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के बीच की दूरी कम हो रही है। इस बदलाव पर अंजना ने कहा कि अब चीजें काफी बदल गई हैं। पहले भी मॉडल फिल्मों में आते थे और अभिनेता मॉडलिंग करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से जुड़े लोग भी अभिनय की दुनिया में आ रहे हैं। किसी व्यक्ति में टैलेंट है और वह सच में अभिनेता बनना चाहता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। आखिर में सबसे जरूरी चीज यह है कि कलाकार अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित कर पाता है या नहीं।

मल्टीस्टारर फिल्मों के बढ़ते चलन पर अंजना ने कहा, ''सबसे जरूरी बात फिल्म की सफलता है। फिल्म छोटी हो या बड़ी और उसमें कितने कलाकार हों, इससे ज्यादा मायने रखता है कि दर्शक उसे पसंद करते हैं या नहीं। जब कोई फिल्म सफल होती है तो इसका फायदा सिर्फ कलाकारों को नहीं बल्कि पूरी टीम को मिलता है। टेक्नीशियन, लाइटिंग टीम, स्पॉट बॉय और प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों को काम मिलता है। मेरी दर्शकों से अपील है कि वे फिल्मों को थिएटर में जाकर जरूर देखें।'' अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने के अनुभव को याद करते हुए अंजना ने कहा, ''यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। करियर शुरू होने के कुछ सालों बाद मुझे अमिताभ बच्चन के साथ विज्ञापन करने का मौका मिला और बाद में राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'डिपार्टमेंट' में भी उनके साथ काम किया। अमिताभ बच्चन और इम्तियाज अली जैसे दिग्गजों के साथ काम करना बड़ी उपलब्धियों में शामिल है।'' हिंदी और साउथ सिनेमा के अंतर पर अंजना ने कहा कि दोनों जगहों की कहानी कहने का तरीका अलग है। हिंदी फिल्में अक्सर पूरे देश के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जबकि क्षेत्रीय सिनेमा अपनी भाषा और संस्कृति से ज्यादा जुड़ा होता है। भारत की यही विविधता उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और कलाकारों को अलग-अलग भाषाओं में काम करने का मौका मिलना एक अच्छी बात है।

कर्म के उदय से नहीं, कर्म के बंध से डरना सीखें : आचार्य कुलबोधिसूरिश्वरजी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। श्री वेपेरी श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ में विराजित आचार्यश्री कुलबोधिसूरिश्वरजी म.सा. ने बुधवार को विश्वकल्याण की मंगलभावना के साथ शांतिधारा पाठ एवं महामांगलिक का श्रवण कराया तथा वासक्षेप द्वारा सभी श्रद्धालुओं को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि शांतिधारा पाठ के श्रवण मात्र से अनेक कार्य सिद्ध एवं सफल होते हैं। महामांगलिक के लाभार्थी हस्तीमल एंड कंपनी के सुमतिबाई प्रेमचंद बंदामुथा परिवार रहे। धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो वस्तु सहजता से प्राप्त हो जाए वह सुलभ कहलाती है, जबकि जिसे पाने के लिए पुरुषार्थ और कष्ट सहना पड़े, वह दुर्लभ होती है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, जबकि अन्य गतियों में जन्म लेना सुलभ है। सौभाग्य से हमें यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका प्रत्येक क्षण आत्मकल्याण में लगाना चाहिए। आचार्यश्री ने धर्माराधना के तीन सूत्र बताते हुए कहा कि जीवन में वर्क स्मार्टली, वर्क क्रिकली और वर्क सेफली के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अध्यात्म के संदर्भ में स्मार्ट वर्क का अर्थ है ऐसा आचरण, वचन और व्यवहार, जिससे नए कर्मों का बंधन न हो।

उन्होंने कहा कि जीवन की प्रत्येक शुभ अथवा अशुभ प्रवृत्ति में कर्म बंधने की संभावना रहती है और वही कर्म आत्मा से चिपककर भविष्य में उदय रूप में फल देते हैं। प्रश्नात्मक शैली में उन्होंने श्रद्धालुओं से पूछा कि वे कर्म के बंध से डरते हैं या कर्म के उदय से? उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म का बंध करना हमारे हाथ में है, किंतु एक बार कर्म बंध गया तो उसका उदय होकर उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। साधु-साध्वियां कर्म के उदय से नहीं, बल्कि कर्म के बंध से भयभीत रहते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य जयणा (सावधानी एवं जागरूकता) के साथ करना चाहिए, जिससे कर्मबंध न्यूनतम हो।

आचार्यश्री ने प्रेरित करते हुए कहा कि धर्म का कोई भी कार्य कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। दान, तप, स्वाध्याय और धर्माराधना का अवसर मिलते ही उसका लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। प्रवचन में विलंब से पहुंचना भी प्रभु-वचनों के प्रति अनादर है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज का युवा वर्ग यह सोचने लगा है कि धर्म वृद्धावस्था में करेंगे, जबकि जीवन का कोई निश्चित भरोसा नहीं है। इसलिए धर्म का आरंभ आज और अभी से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में ऐसा कार्य करें, जो केवल इस भव ही नहीं, बल्कि परभव में भी कल्याणकारी बने। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा, वक्त सबको मिलता है, जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा कहां मिलती है, वक्त को बदलने के लिए।

एक अच्छे संकल्प के साथ माहेश्वरी महिला संगठन ने आयोजित किया संकल्प मेला

संभावित ग्राहकों ने मेले में जमकर की खरीददारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। माहेश्वरी सभा के माहेश्वरी महिला संगठन ने एक अच्छे उद्देश्य से एक दिवसीय 'महिला संकल्प मेले' का आयोजन किया। महिला सदस्याओं ने महिला सशक्तिकरण व मानवसेवा के संकल्प के साथ ओखलीपुरम स्थित माहेश्वरी भवन में बुधवार को खरीददारी प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें 80 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। इस संकल्प मेले में स्वर्णाभूषण व हीरे के आभूषण, साड़ी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, सौंदर्य प्रसाधन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बेडशीट, कृत्रिम गहने, घरेलू सजावट के सामान, राखी, कांच के सामान, गिफ्ट आइटम से लेकर खाने पीने के अनेक स्टॉल लगाए गए।

सुबह से ही प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में खरीददारों की भीड़ देखी गई और दोपहर को इस संख्या में इजाफा होता गया। इस एक दिवसीय संकल्प मेले में संभावित ग्राहकों विशेषकर महिला व युवतियों ने जमकर खरीददारी की। माहेश्वरी भवन के दो फ्लोर के चार हॉल में सभी स्टॉल लगाए गए। मेले में जयनगर के रायसोनी डायमंड ज्वेलर्स के मालिक रतनचंद बागरेचा द्वारा प्रदर्शित हीरों को महिलाओं ने पसंद किया। इस मेले में बेंगलूरु सहित बीकानेर व अन्य शहरों से भी आई महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। मेले में महिला उद्यमियों ने राजस्थानी, गुजराती व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए जो आकर्षण का केन्द्र बने।

आने वाले त्यौहारों से पहले आयोजित इस मेले का उद्घाटन माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष भगवानदास लाहोटी, कर्नाटक गोवा प्रांतीय महिला संगठन की अध्यक्ष सुनीता लाहोटी, महिला संगठन की अध्यक्ष विजयलक्ष्मी सारड़ा, सचिव शोभा भूतड़ा, माहेश्वरी कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डागा आदि ने भगवान महेश के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी सारड़ा ने सभी दुकानदारों का स्वागत किया तथा मंत्री शोभा भूतड़ा ने बताया कि मेले से बचत धनराशि का जनसेवार्थ के कार्यो के लिए उपयोग में किया जाएगा ।

मलेशियाई महावाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने चेन्नई अमृता का दौरा किया

चेन्नई/दक्षिण भारत । मलेशियाई महावाणिज्य दूतावास के अधिकारी सरवना कुमार कुमारवासगम ने उच्च शिक्षा, छात्र गतिशीलता, अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप और वैश्विक कैरियर के अवसरों में भारत-मलेशिया सहयोग को मजबूत करने के लिए चेन्नई के अमृता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का दौरा किया। यह दौरा चेन्नई अमृता की मलेशियाई विश्वविद्यालयों और उद्योग के साथ बढ़ती साझेदारी पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आतिथ्य और विमानन क्षेत्र के छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसर प्रदान करना है।

इस अवसर पर चेन्नईस अमृता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष आर. बूमिनथन ने महावाणिज्य दूतावास के अधिकारियों का स्वागत करते हुए रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक उद्योग के साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता को एकीकृत करने के संस्थान के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। दोनों अधिकारियों के बीच चर्चा का प्रमुख केंद्र चेन्नईस अमृता और मलेशियाई होटल एसोसिएशन (एमएएच) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) था, जिस पर एमएएच के सीईओ इसहाक मोहन राज ने हस्ताक्षर किया।

अग्रसेन कालेज में ने याद किया कामराज को

चेन्नई/दक्षिण भारत। जयगोविंद हरीगोपाल अग्रवाल अग्रसेन कालेज माधावरम चेन्नई के तमिल विभाग के तत्वावधान मे आज तमिल राजनीति के देदीप्यमान नक्षत्र व सर्वप्रिय पुरोधा श्री कामराज जी का 124 वाँ जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर तमिल विभाग ने एक वर्कशाप का आयोजन किया जिसका विषय था कामराज की उपलब्धियां। इस मौके पर मुख्यअतिथि के रूप में वेल्स साइंस, टेक्नॉलजी एंड अड्वान्स रिसर्च सेंटर के सहायक प्राध्यापक तमिल विभाग के डॉ प्रकाश ने कामराज के गुणों के बारे में बताया। सचिव हरीश कुमार सांघी ने कामराज की सेवाओं को निःस्वार्थ सेवा बताकर उनके बताए रास्ते पर चलने हेतु छात्रों को प्रेरित किया। अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल और कोषाध्यक्ष बालगोविंद गुप्ता ने कामराज को एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप मे याद किया। अपने अध्यक्षीय भाषण मे प्राचार्य डॉ वी गोपी ने छात्रों को कामराज के प्रति सम्मान करने व गर्व करने का संदेश दिया।

सद्गुरु का समागम अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य है : मुनि तीर्थचैतन्य विजय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। किलपॉक श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ में बुधवार प्रातः आचार्यश्री तीर्थभद्र सूरीश्वरजी म.सा. के शिष्यरत्न मुनिश्री तीर्थचैतन्य विजयजी म.सा. एवं साध्वीश्री पूर्णभद्राश्रीजी का भव्य चातुर्मास प्रवेश श्रद्धा, भक्ति और उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मेघजीवी भवन से सुसज्जित वरघोड़ा निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ मुनिसुव्रत स्वामी जिनालय पहुंचा। वहां धर्मसभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के प्रारंभ में संघ के चेयरमैन शांतिलाल जैन तथा अध्यक्ष अरुण ओस्तवाल ने श्रमण-श्रमणीवृंद का भावपूर्ण स्वागत करते हुए सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुनिश्री तीर्थचैतन्य विजयजी म.सा. ने श्रद्धालुओं को चातुर्मास के पावन अवसर का अधिकतम सदुपयोग करते हुए धर्म, आराधना, स्वाध्याय और संयम से जुड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सद्गुरु का सान्निध्य मिलना अत्यंत सौभाग्य की बात है। सद्गुरु के मार्गदर्शन में जीवन का प्रत्येक क्षण आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर होता है। एक प्रेरक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया कि सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रति बहरे और उदासीन बनने से ही आत्मा की निर्मलता का विकास होता है।

इस अवसर पर लाभार्थी परिवारों ने श्रमण-श्रमणीवृंद का गुरुपूजन कर श्रद्धापूर्वक कांबली अर्पित की। वरघोड़ा के लाभार्थी जीवीबाई मेघराज साकरिया परिवार, कलश के लाभार्थी संघवी शांतिलाल सोकलचंद जैन परिवार तथा गंहुली के लाभार्थी संतोषबेन भेरुलाल कोठारी परिवार का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में किरण राठौड़ एवं सिद्धार्थ कोचर ने भक्तिमय संगीत की मनोहारी प्रस्तुति देकर वातावरण को धर्ममय बना दिया। अंत में संघ सचिव मुकेश शाह ने सभी अतिथियों, लाभार्थी परिवारों एवं उपस्थित श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रभात फेरी के माध्यम से छात्रों ने दिया नशामुक्ति एवं शिक्षा का संदेश

चेन्नई/दक्षिण भारत । यहां एजी जैन विद्यालय के विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति अभियान एवं शिक्षा जागरूकता विषय पर एक प्रभावशाली प्रभात फेरी का आयोजन किया। प्रातःकालीन बेला में विद्यालय परिसर से आरंभ हुई इस जागरूकता यात्रा में विद्यार्थियों ने हाथों में आकर्षक तख्तियाँ एवं प्रेरणादायी नारों के साथ नगरवासियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया तथा शिक्षा के महत्व का प्रभावी संदेश दिया। नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, शिक्षित समाज, समृद्ध राष्ट्र, ज्ञान का प्रकाश ही जीवन का वास्तविक विकास है जैसे नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। इसके साथ ही विद्यालय में कामराज का जन्मदिवस भी अनन्य हर्षोल्लास के साथ मनाया गया उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ जयश्री एवं सचिव दलजीत सिंह ढढा ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के बारे अवगत कराते हुए जागरूक बनने तथा समाज को भी नशामुक्त और शिक्षित बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

स्थानांग सूत्र पर डॉ. दिलीप धींग के दो शोधालेख चयनित

चेन्नई/दक्षिण भारत।। श्रुत रत्नाकर, अहमदाबाद द्वारा शास्त्रीय भाषा प्राकृत के प्राचीन आगम 'स्थानांग सूत्र' पर ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है। शोधपत्र प्रकाशन योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्राकृत केन्द्र के पूर्व निदेशक साहित्यकार डॉ. दिलीप धींग द्वारा लिखित दो शोध-निबंधों का चयन किया गया है। ग्राम धर्म, राष्ट्र धर्म आदि दस धर्म तथा समाचारी विषय पर 27 पृष्ठों में लिखित ये निबंध डॉ. धींग द्वारा गोहाना (2024) और आगरा (2025) में हुई राष्ट्रीय प्राकृत संगोष्ठियों में प्रशंसित हो चुके हैं। जैनविद्या की सर्वाधिक लोकप्रिय शोध पत्रिका 'जिनवाणी' और 'श्रमण संस्कृति' में भी डॉ. धींग के ये शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। श्रुत रत्नाकर के निदेशक डॉ. जितेन्द्र बी. शाह ने पत्र में लिखा कि डॉ. धींग ने प्रस्तुत शोधपत्रों में विषय की गहनता, प्रासंगिकता एवं मौलिक चिंतन के माध्यम से संगोष्ठी की शैक्षणिक गरिमा को समृद्ध किया है।

डॉ मुनि पुलकित कुमार का 19 को होगा चातुर्मासिक प्रवेश

चेन्नई/दक्षिण भारत। यहां आचार्यश्री महाश्रमण के शिष्य डॉ मुनिश्री पुलकित कुमारजी 'नचिकेता' मुनिश्री आदित्य कुमार का किलपॉक के भिक्षु निलयम कुबेर में 19 जुलाई को चातुर्मासिक मंगल प्रवेश होगा। तेरापंथ सभा चेन्नई के अध्यक्ष महेंद्र मांडोत के निवास स्थान से सुबह चातुर्मासिक मंगल प्रवेश रैली के रूप में होगा।

मल्टीलेवल स्पाइनल स्टेनोसिस से पीड़ित रोगी के इलाज में डाक्टरों को मिली सफलता

चेन्नई। सिम्स अस्पताल के विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक सर्जनों ने मल्टी-लेवल स्पाइनल स्टेनोसिस और डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस से पीड़ित 84 वर्षीय मरीज पर उन्नत सिंगल-इंसिजन एंडोस्कोपिक प्रक्रिया से इलाज कर मरीज को नया जीवन दान दिया है। रीढ़ की हड्डी की विकृति के कारण मरीज की कमर की नसें बुरी तरह दब गई थीं और वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गया था। सिम्स अस्पताल के डाक्टरों ने 8 मिमी के चीरे के माध्यम से की गई इस उन्नत यूनिपॉर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन प्रक्रिया से दबाव को कम किया और मरीज को फिर से चलने-फिरने में सक्षम बनाया यह प्रक्रिया अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. जी. वेंकटेश कुमार और डॉ. विघ्नेश जयबालन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ सहित एक बहुविषयक टीम द्वारा संपन्न की गई।सर्जरी प्रक्रिया के बारे में बताते हुए।

डॉ. वेंकटेश कुमार ने कहा कि मरीज गंभीर शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त था जांच में गंभीर अपक्षयी स्कोलियोसिस का पता चला, जो रीढ़ की हड्डी की एक विकृति है जिसके कारण कमर के क्षेत्र में नसों पर काफी दबाव बढ़ता है। उन्होंने कहा कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी में हुई प्रगति ने केवल 8 मिमी के एक चीरे के माध्यम से पूर्ण एंडोस्कोपिक यूनिपॉर्टल लम्बर स्टेनोसिस डीकंप्रेशन करने में सक्षम बनाया। इस प्रक्रिया से नसों पर पड़ने वाला दबाव सफलतापूर्वक कम हो गया और मरीज कुछ ही समय बाद दर्द रहित होकर चलने-फिरने लगा। डॉ. विघ्नेश जयबालन ने इस प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि पारंपरिक ओपन स्पाइन सर्जरी की तुलना में उन्नत एंडोस्कोपिक तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सामान्य ऊतकों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाए बिना वांछित परिणाम प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया में रक्तस्राव बहुत कम होता है, मांसपेशियों को नहीं हटाया जाता, ऑपरेशन के बाद कम दर्द होता है, टांके नहीं लगते और रोगी तेजी से रिकवर करता है। सिम्स अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. रवि पचामुथु ने इस अवसर पर कहा कि यह मामला नवाचार और बहुविषयक सहयोग के माध्यम से उन्नत, रोगी-केंद्रित देखभाल प्रदान करने के लिए सिम्स अस्पताल की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है।उन्होंने कहा कि सिम्स अस्पताल सबसे जटिल मामलों में भी विश्व स्तरीय देखभाल प्रदान करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और नैदानिक उत्कृष्टता में निवेश करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं।

अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता 'प्रगति 2026' सम्पन्न

चेन्नई। यहां 15 जुलाई को सनातन धर्म एसोशिएसन के तत्वावधान में संचालित मोतीलाल फोमरा सनातन धर्म हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रांगण में प्रगति अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के छात्रों द्वारा भव्य नृत्य की प्रस्तुति देकर, आगन्तुकों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथिआनंदम यूथ फाउन्डेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष आनंद सेल्व कुमार रहे। मंजू सारड़ा ने सभी का स्वागत किया। पत्राचारक विजय माहेश्वरी ने मुख्य अतिथि का सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में निर्णायक गणों का सम्मान भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर विद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में जूनियर एवं सीनियर वर्ग में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जिसमें विजयी प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को शील्ड और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में 27 विद्यालयों के 349 छात्र, छात्राओं ने प्रतिभागी बनकर कार्यक्रम को सफलता के शिखर तक पहुंचा। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में संस्था के अध्यक्ष श्री आर के झवर , पत्राचारक विजय माहेश्वरी, एसएम दम्मानी, एस. पी. बाहेती, आर. सी. डागा, सुनील डागा, के.एल. डागा, करुणा मोहता आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अन्त में वन्दना भट्टड ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

आमंत्रण

बेंगलूरु के कर्नाटक इनरवियर एसोसिएशन(किया) बेंगलूरु के अध्यक्ष महावीरचन्द मेहता व उपाध्यक्ष अश्विन सेमलानी ने बेंगलूरु प्रवास पर आए हुब्बली के समाजसेवी महेन्द्र सिंघी से मुलाकात कर उन्हें कर्नाटक इनरवियर ट्रेड फेयर में अतिथि के रूप में शामिल होने का निवेदन किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश चोपड़ा, संयुक्त कोषाध्यक्ष विनोद चौहान सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.